रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73 REGISTERED NO. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1976/चैत्र 28, 1898
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1976/CHAITRA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

का०आ० 1346:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, श्री पी० पी० श्रीवास्तव, खण्ड आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/हि०प्र०/76]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 20th March, 1976

S.O. 1346.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission of India, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby nominates Shri P. P. Srivastava, Divisional Commissioner, Himachal Pradesh, as the Chief Electoral Officer with effect from the date he takes charge of the office and until further orders.

[No. 154/HP/76]

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का०आ० 1347—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 165-महुवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मदनभाई उदैसिंह चौधरी, डूंगरी (पानाफलिया), पोस्ट वनस्काई, ताल्लुका महुवा, जिला सूरत (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मदनभाई उदैसिंह चौधरी को संसद

5 GI/76—1

के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान-परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० गुज०-वि०स०/165/75(36)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1347.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madanbhai Udesing Chaudhary, At Dungri (Panafalia), Post Vanskui, Taluka Mahuva, District Surat (Gujarat), a contesting candidate for general election to the Gujarat Legislative Assembly from 165-Mahuva Constituency, held in June, 1975 has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Madanbhai Udesing Chaudhary to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/165/75(36)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का०आ० 1348.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-उम्रेठ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीरामाभाई णानाभाई सोलंकी, बालपुरा, जूना रास्ता, आनन्द, जिला कैरा (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामाभाई णानाभाई सोलंकी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गुज०-वि०स०/127/75(37)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 1348.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramabhai Shanabhai Solanki, Balupura, Juna Rasta, Anand, District Kaira (Gujarat), a contesting candidate for general election to the Gujarat Legislative Assembly from 127-Umreth Constituency held in June, 1975 has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramabhai Shanabhai Solanki to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/127/75(37)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1976

का०आ० 1349.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), और नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने इस अधिसूचना के द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 28 फरवरी, 1957 के आदेश संख्या का० नि० आ० 627 में नीचे लिखे संशोधन किए हैं, अर्थात्

उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में;

(क) भाग I, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात :—

1	3	3	4
"बैंक नोट प्रेस देवास सभी पद	महाप्रबन्धक, बैंक नोट प्रेस, देवास	महाप्रबन्धक, बैंक नोट प्रेस, देवास	सभी"

ख. भाग II, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :

1	2	3	4	5
"बैंक नोट प्रेस, देवास । कनिष्ठ पर्यवेक्षक, निरीक्षक नियंत्रण, एंग्रेवर, स्टोर-कीपर, सहायक स्टोरकीपर, कनिष्ठ कलाकार, बैन और] ट्रक ड्राइवर 260-400 रु० या इससे अधिक के ग्रेड के अवर्गीकृत औद्योगिक पद	मुख्य लेखा और प्रशासनिक अधिकारी,	उप-महाप्रबंधक	सभी	महाप्रबन्धक

सभी अन्य पद	मुख्य लेखा और प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य लेखा और प्रशासनिक अधिकारी	सभी	महाप्रबन्धक"

(ग) भाग III में, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात्:—

1	2	3	4	5
"बैंक नोट प्रेस, देवास सभी वर्गीकृत पद	कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य लेखा और प्रशासनिक अधिकारी	सभी	उप महाप्रबन्धक
225-308 और उससे कम के ग्रेड के सभी अवर्गीकृत औद्योगिक पद	कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	चीफ केमिस्ट या वर्क्स मैनेजर	सभी	उप महाप्रबंधक"

[फा० सं० एफ० 10/21/73-बी०नो०प्रे०]

के० सी० सोढिया, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Deptt. of Economic Affairs)

New Delhi, the 26th March, 1976

S. O. 1349.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, and clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1)of rule 24, of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.R.O. 627 dated the 28th February, 1957, namely :

In the Schedule to the said order,—

(a) in Part I, the following entries shall be added at the end, namely :—

1	2	3	4
"Bank Note Press Dewas. All posts	General Manager, Bank Note Press, Dewas	General Manager, Bank Note Press, Dewas	All";

(b) in Part II, the following entries shall be added at the end, namely :—

1	2	3	4	5
"Bank Note Press, Dewas. Junior Supervisor, Inspector Control, Engraver, Store Keeper, Assistant Store Keeper, Junior Artist, Van & Truck Driver, Unclassified Industrial posts in the grade of Rs. 260-400 and above.	Chief Accounts and Administrative Officer	Deputy General Manager	All	General Manager
All other posts	Chief Accounts and Administrative Officer	Chief Accounts and Administrative Officer	All	General Manager.

(c) in Part III, the following entries shall be added at the end, namely :—

1	2	3	4	5
"Bank Note Press Dewas. All Classified posts	Junior Administrative Officer	Chief Accounts and Administrative Officer Officer	All	Deputy General Manager
All Unclassified Industrial posts in the grade of Rs. 225-308 and below	Junior Administrative Officer	Chief Chemist or Works Manager	All	Deputy General Manager."

[File No. F.10/21/73-BNP.]

K.C. SODHIA, Dy. Secy.

नयी दिल्ली, 31 मार्च, 1976

(बीमा)

का०आ० 1350—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 734, तारीख 23 अगस्त, 1958 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को यथा लागू बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 27क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इण्डस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए जाने वाले 2 50 करोड़ रुपये के मूल्य के 6 प्रतिशत के 10 वर्षीय बन्धपत्र 1986 को (2.50 करोड़ रुपये से ऊपर 10 प्रतिशत तक प्राप्त किए गए अभिदाय को रखने के अधिकार सहित) उपरोक्त धारा के प्रयोजनार्थ "अनुसूचित विनिधान" के रूप में घोषित करती है।

[फा० सं० 88(18)बीमा-IV/76-I]

New Delhi, the 31st March, 1976

(INSURANCE)

S.O. 1350.—In exercise of the powers conferred by Clause (q) of sub-section (1) of section 27(A) of the Insurance

Act, 1938 (4 of 1938) as applied to Life Insurance Corporation of India by the Notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) No. G.S.R. 734 dated the 23rd August, 1958, the Central Government hereby declares the 6 per cent, 10 years Bonds 1986, of the value of Rs. 2.50 crores to be issued in 1975-76 (with the right to retain the subscription received upto 10 per cent in excess of Rs. 2.50 crores) by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. as "Scheduled Investment" for the purposes of the above section.

[No. F. 88(18) Ins. IV/76-I]

का०आ० 1351.—केन्द्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27ख की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा 1975-76 में जारी किए जाने वाले 2.50 करोड़ रुपये के मूल्य के 6 प्रतिशत के 10 वर्षीय बन्ध पत्र 1986 को (2 50 करोड़ से ऊपर 10 प्रतिशत प्राप्त किए गए अभिदाय को रखने के अधिकार सहित) उपरोक्त धारा के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित विनिधान" के रूप में घोषित करती है।

[फा० सं० 88(18)विनि० IV/76-2]

आर० डी० खानवलकर, अवर सचिव

INSURANCE

S.O. 1351.—In exercise of the powers conferred by Clause (j) of Sub-section (1) of Section 27B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby declares the 6 per cent—10 years Bonds 1986 of the value of Rs. 2.50 crores to be issued in 1975-76 (with the right to retain the subscription received upto 10 per cent in excess of Rs. 2.50 crores) by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. as "Approved Investment" for the purposes of above section.

[No. F. 88(18) Ins. IV/76-II]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का०आ० 1352—पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29 वां) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है अर्थात्:—

1. इस आदेश को, पूंजी निर्गम (छूट) संशोधन आदेश, 1976 कहा जाएगा ।

2. पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 में—

(क) खण्ड 3 के परन्तुक में, "25 लाख रुपए" के अक्षरों, अंको और शब्दो के स्थान पर "पचास लाख रुपए" शब्द रख दिए जाएंगे;

(ख) खण्ड 4 मे "पचीस लाख रुपए" शब्दो के स्थान पर जहां कहीं भी वे शब्द आए। "पचास लाख रुपए" शब्द रख दिए जायेंगे ।

(ग) खण्ड 5 में, शुरू के पैराग्राफ में "पचीस लाख रुपए" शब्दो के स्थान पर "पचास लाख रुपए" शब्द रख दिए जाएंगे।

[संख्या एफ 2(4)—सी सी आई/76]

जे० पी० मुखर्जी, अपर नयलिक

OFFICE OF THE CONTROLLER OF CAPITAL ISSUES

New Delhi, the 1st April, 1976

S.O. 1352.—In exercise of the powers conferred by sub-section (II) of secton 6 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, namely :—

1. This Order may be called the Capital Issue (Exemption) Amendment Order, 1976.

2. In the Capital Issues (Exemption) Order, 1969—

(a) in the proviso to clause 3, for the letters, figures and word "Rs. 25 lakhs" the words "fifty lakhs of rupees" shall be substituted;

(b) in clause 4, for the words 'twenty five lakhs of rupees" wherever they occur, the words "fifty lakhs of rupees" shall be substituted;

(c) in clause 5, in the opening paragraph for the words "rupees twenty five lakhs" the words "fifty lakhs of rupees" shall be substituted.

[No. F. 2(4)-CCI/76]

J. P. MUKHERJEE, Additional Controller

राजस्व और बैंकिंग विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1976

स्टाम्प

का० आ० 1353—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम को, उक्त निगम द्वारा जारी किए गए पचपन लाख रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बन्ध पत्रों पर स्टाम्प-शुल्क मद्दे प्रभार्य इकतालिस हजार, दो सौ पचास रुपये समेकित स्टाम्प-शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा देती है।

[सं० 18/76-स्टाम्प/फ०स० 471/11/76-सीमाशुल्क VIII]

डी० के० आचार्य, अवर सचिव

(Department of Revenue and Banking)

ORDER

New Delhi, the 7th April, 1976

STAMPS

S.O. 1353.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamps Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of forty one thousand, two hundred and fifty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of fifty-five lakhs of rupees issued by the said Corporation.

[No. 18/76-Stamps-F. No. 471/11/76-Cus.VII]

D. K. ACHARYYA, Under Secy.

बैंकिंग विभाग

नयी दिल्ली, 12 फरवरी 1976

आय-कर

का०आ० 1353—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को विहित प्राधिकारी, सचिव,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

दकन शुगर टैक्नोलोजिस्टस एसोसिएशन, पुणे

यह अधिसूचना 1-4-1974 से 31-3-1977 तक प्रभावी है।

[सं० 1226—फा०सं० 203/74/74-आई टी ए II]

(Department of Revenue & Banking)

New Delhi, the 12th February, 1976

INCOME TAX

S.O. 1354.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

DECCAN SUGAR TECHNOLOGISTS ASSOCIATION, POONA.

This notification is effective from 1-4-74 to 31-3-1977.

[No. 1226—F. No. 203/74/74-ITA. II]

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976

का०आ० 1355—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को, विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है। यह केन्द्र अपने अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाकलापों और उन पर उपगत व्यय की बाबत परिषद को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

संस्था

मधुमेह अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

यह अधिसूचना इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 1239—फा०सं० 203/16/76-आ०क०अ० II]

टी०पी० झुनझुनवाला, उप सचिव

New Delhi, the 21st February, 1976

S.O. 1355.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, for research purposes only. The Centre will submit annual report about its research activities and the expenditure incurred thereon to the Council.

INSTITUTION

DIABETES RESEARCH CENTRE, MADRAS.

This notification is effective for a period of two years from the date of this Notification.

[No. 1239—F. No. 203/16/76-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1976

का०आ० 1356—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को विहित प्राधिकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा 2क के प्रयोजनार्थ, निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है:

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम	: तमिलनाडु में लुगदीकरण उद्योगों की आवश्यकताओं के प्रतिनिर्देश से वृक्ष अभिवृद्धि पर अनुसंधान परियोजना।
(क) प्रायोजक	: दी शेवशायी पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड, डाकघर सलेम, जिला इरोड।
(ख) प्रायोजना का स्थान	: तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर।
अनुसंधान कार्यक्रम की अवधि	: 1976-85
प्राक्कलित व्यय	: 11,21,600 रु० (पूरी अवधि के लिए) 1,90,370 रु० (1976 के लिए)

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, जहां उपर्युक्त कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i)(ii) के अधीन वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 878 (फा०सं० 203/39/75-आ०क०अ० II) तारीख 18 अप्रैल, 1975 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

[सं० 1234—फा०सं० 203/1/76-आ०क०अ० II]

New Delhi, the 17th February, 1976

S.O.1356.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 by the prescribed authority, the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi :

Scientific Research Programme :	Research Projection Tree Improvement with reference to the needs of pulping Industries in Tamilnadu.
Sponsored (a) by :	The Seshssayee Paper & Boards Ltd., P.O. Salem, District Erode.
Sponsored (b) at :	Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
Duration of Research Programme :	1976-85.
Estimated expenditure :	Rs. 11,21,600 (for full period) Rs. 1,90,370 (for 1976)

Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, where the above programme has been sponsored has been approved under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance Notification No. 878 (F. No. 203/39/75-I.T.A. II) dated 18th April, 1975.

[No. 1234—F. No. 203/1/76-I.T.A.II]

नयी दिल्ली, 19 फरवरी, 1976

का० आ० 1357.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ केवल अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है। यह संस्था अपने अनुसंधान क्रियाकलापों की बाबत वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां परिषद को भेजेगी।

संस्था

कैलाश सेवा सदन, मुम्बई

यह अधिसूचना इस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी ।

[सं० 1236—फा० सं० 203/60/75-आ०क०अ० II]

के० आर० राघवन, निदेशक

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 1357.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, for research purposes only. The institution will submit annual reports and returns about its research activities to the Council.

INSTITUTION

KAILAS SEVA SADAN, BOMBAY.

This notification is effective for a period of two years from this date.

[No. 1236—F. No. 203/60/75-ITA. II]

K. R. RAGHAVAN, Director

नयी दिल्ली, 31 मार्च, 1976

बैंकिंग

का०आ० 1358.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा के अध्यक्ष के रूप में श्री दिलीप मुकर्जी की नियुक्ति से सम्बन्धित 2 अक्तूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या एफ० 4-11/75-ए०सी०-1 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "31 मार्च, 1976" के अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1976" के अंकों, अक्षरों और शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० एफ० 4-11/75-ए०सी०]

New Delhi, the 31st March, 1976

BANKING

S.O. 1358.—In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 34, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking No. F. 4-11/75-AC-I, dated the 2nd October, 1975 relating to the appointment of Shri Dilip Mukherjee as the Chairman of the Gaur Gramin Bank, Malda, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1976", the figures, letters and word "30th September, 1976" shall be substituted.

[No. F. 4-11/75-AC]

का०आ० 1359.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के अध्यक्ष के रूप मे श्री एस०एल० जैन की नियुक्ति से सम्बन्धित 2 अक्तूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या एफ० 4-12-75-ए०सी०-1 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "31 मार्च, 1976" के अंको, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1976" के अकों, अक्षरों और शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० एफ० 4-12/75-ए०सी०]

S.O. 1359.—In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 34, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 4-12/75-AC I, dated the 2nd October, 1975 relating to the appointment of Shri S. L. Jain as the Chairman of the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1976", the figures, letters and word "30th September, 1976" shall be substituted.

[No. F. 4-12/75-AC]

का०आ० 1360.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री के० डी० अग्रवाल की नियुक्ति से सम्बन्धित 2 अक्तूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या एफ० 4-13/75-ए०सी०-1 में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में "31 मार्च, 1976" के अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1976" के अका, अक्षरो और शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० एफ० 4-13/75-ए०सी]

S.O. 1360.—In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 34, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 4-13/75-AC-I, dated the 2nd October, 1975 relating to the appointment of Shri K. D. Agarwal as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1976", the figures, letters and word "30th September, 1976" shall be substiuted.

[No. F. 4-13/75-AC]

का०आ० 1361.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की प्रथमा बैंक, मुरादाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० दस्तगीर की नियुक्ति से सम्बन्धित 21 दिसम्बर, 1975

की अधिसूचना संख्या एफ० 4-15/75-ए०सी० में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "31 मार्च, 1976" के अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1976" के अंकों, अक्षरों और शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० एफ० 4-15/75-ए० सी०]

S.O. 1361.—In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 34, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 4-15/75-AC, dated the 24th December, 1975 relating to the appointment of Shri S. R. Dastgir as the Chairman of the Prathama Bank, Moradabad, namely :-

In the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1976", the figures, letters and word "30th September, 1976" shall be substituted.

[No. F. 4-15/75-AC]

का०आ० 1362—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आज़मगढ़ के अध्यक्ष के रूप में श्री हसन किदवई की नियुक्ति से सम्बन्धित 6 जनवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या एफ० 4-91/75-ए० सी० (VI) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना मे "31 मार्च, 1976" के अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 1976" के अंकों, अक्षरो और शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० एफ० 4-91/75-ए०सी०]

S.O. 1362.—In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 34, of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. F. 4-91/75-AC (VI), dated the 6th January, 1976 relating to the appointment of Shri Hasan Kidwai as the Chairman of the Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and word "31st March, 1976", the figures, letters and word "30th September, 1976" shall be substituted.

[No. F. 4-91/75-AC]

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का०आ० 1363.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एस० के० खन्ना को हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 अप्रैल, 1976 से आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमे उक्त श्री एस० के० खन्ना अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 4-14/75-ए० सी०]
कु० भवानी, उप सचिव

New Delhi, the 1st April, 1976

S.O. 1363.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Khanna as the Chairman of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani, and specifies the period commencing on the 1st April, 1976 and ending with the 30th September, 1976 as the period for which the said Shri S. K. Khanna shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-14/75-AC]
K. BAVANI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का०आ० 1364.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड 3(1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री जी० लक्ष्मीनारायणन को 1 अप्रैल, 1976 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1976 को समाप्त होने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए, इण्डियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/3/76-बी० ओ० 1]

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 1364.—In pursuance of sub-clause, (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri G. Lakshminarayanan as the Managing Director of Indian Bank for a further period commencing on 1st April, 1976 and ending with 30th April, 1976.

[No. F. 9/3/76-BO.I]

का०आ० 1335—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री जी० लक्ष्मीनारायणन को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1976 से इण्डियन बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से इण्डियन बैंक के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/3/76-बी०ओ० 1(2)]
निमलचन्द्र सेन गुप्ता, सचिव

S.O. 1365.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri G. Lakshminarayanan, who has been re-appointed as Managing Director of Indian Bank with effect from 1st April, 1976, to be the Chairman of the Board of Directors of Indian Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/3/76-BO.I(2)]
N. C. SEN GUPTA, Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1976

का०आ० 1366.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में मार्च 1976 के दिनांक 19 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	19,10,97,000		सोने का सिक्का और बुलियन :		
			(क) भारत में रखा हुआ .	182,52,51,000	
संचलन में नोट . .	6611,19,96,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियां . .	271,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट .		6630,30,93,000			
			जोड़ . .		454,26,48,000
			रुपये का सिक्का . .		10,59,96,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . .		6165,44,49,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र . .		..
कुल देयताएं . .		6630,30,93,000	कुल आस्तियां . .		6630,30,93,000

के० आर० पुरी, गवर्नर

दिनांक : 24 मार्च, 1976

19 मार्च, 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	19,10,97,000
		रुपये का सिक्का	2,63,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	छोटा सिक्का	4,47,000
		खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि .	334,00,00,000	(क) देशी	176,35,87,000
		(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि . .	140,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल . . .	432,26,01,000
		विदेशों में रखा हुआ बकाया* . . .	1175,20,37,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	निवेश**	387,50,32,000
		ऋण और अग्रिम :	
जमाराशियां :		(i) केन्द्रीय सरकार को . . .	..
		(ii) राज्य सरकारों को† . . .	194,90,53,000
(क) सरकारी :		ऋण और अग्रिम :	
		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को× . .	887,12,00,000
(i) केन्द्रीय सरकार . . .	560,77,37,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को×× . .	375,36,81,000
		(ii) दूसरों को	12,95,37,000
(ii) राज्य सरकारे . . .	5,23,83,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
(ख) बैंक :		(क) ऋण और अग्रिम :	
		(i) राज्य सरकारों को . .	69,33,94,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . .	571,03,94,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . .	15,13,49,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . .	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	21,61,10,000	(iv) कृषि पुनर्वास और विकास निगम को .	85,30,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,11,46,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक .	1,55,94,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	

देयताएं		रुपये	आस्तियां		रुपये
(iv) अन्य बैंक		72,70,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम		87,95,18,000
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से		
(ग) अन्य		1576,59,93,000	ऋण, अग्रिम और निवेश		
			(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम		380,14,32,000
देय बिल		147,32,58,000	(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश		..
अन्य देयताएं		933,68,02,000	अन्य आस्तियां		528,71,67,000
	रुपये	4837,55,41,000		रुपये	4837,55,41,000

*नकदी, अवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल है ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है ।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल है ।

×भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 29,52,00,000/- रुपये शामिल है ।

××राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है ।

दिनांक : 24 मार्च, 1976

के० आर० पुरी, गवर्नर

[सं० फ० 10(1)/76-बी० ओ० I]

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 29th March, 1976

S.O. 1366.—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 19th day of March 1976

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	19,10,97,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6611,19,96,000		(a) Held in India	182,52,51,000	
			(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	271,73,97,000	
Total notes issued		6630,30,93,000			
			Total		454,26,48,000
			Rupee Coin		10,59,96,000
			Government of India Rupee Securities		6165,44,49,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6630,30,93,000	Total Assets		6630,30,93,000

K. R. PURI, Governor

Dated the 24th day of March, 1976.

Statement of the affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 19th March, 1976

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	19,10,97,000
		Rupee Coin	2,63,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,47,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	176,35,87,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	432,26,01,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	1175,20,37,000
		Investigations**	387,50,32,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments @	194,90,53,000
		Loans and Advances to :—	
Deposits :—		(i) Scheduled Commercial Banks†	887,12,00,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks‡	375,36,81,000
(i) Central Government	560,77,37,000	(iii) Others	12,95,37,000
(ii) State Governments	5,23,83,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks			
(i) Scheduled Commercial Banks	571,03,94,000	(a) Loans and Advances to :—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	21,61,10,000	(i) State Governments	69,33,94,000
(iii) non-Scheduled State Co-operative Banks	1,55,94,000	(ii) State Co-operative Banks	15,13,49,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	72,70,000	(iv) Agricultural Refinance & Development Corporation	85,30,00,000
(c) Others	1576,59,93,000		
Bills Payable	147,32,58,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,11,46,000
Other Liabilities	933,68,02,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	87,95,18,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	380,14,32,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	528,71,67,000
Rupees	4837,55,41,000	Rupees	4837,55,41,000

* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

** Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 29,52,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Csedit (Stabilisation) Fund.

K.R. PURI, Governor

[No. F. 10(1)/76-B.O. I]

Dated the 24th day of March, 1976.

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1976

का०आ० 1367.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री रघबीर चन्द खन्ना को फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29 मार्च, 1976 से आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमे श्री रघबीर चन्द खन्ना अध्यक्ष के रूप मे कार्य करेंगे ।

[स० एफ० 4-90/75 ए० सी० (4)]

New Delhi, the 29th March, 1976

S.O. 1367.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government appoints Shri Raghbir Chand Khanna as the Chairman of the Farrukhabad Gramin Bank and specifies the period commencing on the 29th March, 1976 and ending with the 30th September, 1976 as the period for which the said Shri Raghbir Chand Khanna shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-90/75-AC(IV)]

का०आ० 1368—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री श्याम चन्द्र सोनी को राय बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29 मार्च, 1976 से आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमे श्री श्याम चन्द्र सोनी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एफ० 4-92/75-ए० सी० (4)]

के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव

S.O. 1368.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government appoints Shri Shyam Chandra Soni as the Chairman of the Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank and specifies the period commencing on the 29th March, 1976 and ending with the 30th September, 1976 as the period for which the said Shri Shyam Chandra Soni shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-92/75-AC (IV)]

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1976

का०आ० 1369.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्न सारणी के कालम (1) मे उल्लिखित उन अधिकारियो को नियुक्त करती है जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी होगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सम्पदा अधिकारी (एस्टेट आफीसर) होगे । ये अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उक्त सारणी के कालम (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानो के सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारियो (एस्टेट आफीसर) को सौंपे गये कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पद	सरकारी स्थानों की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाये
(1)	(2)
1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, 16, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यो तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्रों मे अवस्थित स्थान ।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, रूबी हाउस, 8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1 ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय राज्यो में अवस्थित स्थान ।
3 क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, 4, पार्क रोड़, लखनऊ ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित स्थान ।
4 क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, 150-ए/2, चोरडिया मैंशन, माउन्ट रोड, मद्रास ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यो तथा संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी में अवस्थित स्थान ।
5 क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, आयकर कार्यालय के सामने, गांधी ब्रिज के पास, नवजीवन पोस्ट आफिस, अहमदाबाद ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और गुजरात राज्य मे अवस्थित स्थान ।
6 क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, फ्लैट न० 272, पीपल्स मोबाइल अस्पताल भवन, डा० एनीबेसेन्ट रोड़, वर्ली, बम्बई ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और महाराष्ट्र राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र गोआ मे अवस्थित स्थान ।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक (मध्य प्रदेश और दिल्ली) बैंक आफ बड़ौदा, 16, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और मध्य प्रदेश राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित स्थान ।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पंजाब, हरयाणा, जम्मू व कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़), बैंक आफ बड़ौदा, 16, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नयी दिल्ली ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और पजाब, हरयाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ मे अवस्थित स्थान

(1)	(2)
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, सेठी सदन, 7, पार्क हाउस स्कीम, मिर्जा इस्माइल रोड़, जयपुर-1	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और राजस्थान राज्य मे अवस्थित स्थान ।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पश्चिम बंगाल), बैंक आफ बड़ौदा, रूबी हाउस, 8, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और पश्चिम बंगाल राज्य मे अवस्थित स्थान ।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक (बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय), बैंक आफ बड़ौदा, रूबी हाउस, 8, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय राज्य मे अवस्थित स्थान ।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पश्चिमी जिले) बैंक आफ बड़ौदा, 4, पार्क रोड़, लखनऊ ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और उत्तर प्रदेश राज्य के नैनीताल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर और बुलन्दशहर जिलो मे अवस्थित स्थान ।
13. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पूर्वी जिले), बैंक आफ बड़ौदा, पोस्ट बाक्स नं० 198, 4, पार्क रोड़, लखनऊ ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और उत्तर प्रदेश राज्य के राय बरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और झासी जिलो मे अवस्थित स्थान ।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी), बैंक आफ बड़ौदा, 150-ए/2, चौरडिया मैंशन, माउन्ट रोड़, मद्रास-2 ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और तमिलनाडु राज्य और संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी मे अवस्थित स्थान ।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल) बैंक आफ बड़ौदा, सीट कालिज एवेन्यू, टोयनापेट, मद्रास ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यो मे अवस्थित स्थान ।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक (मध्य क्षेत्र), बैंक आफ बड़ौदा, आयकर कार्यालय के सामने, गांधी ब्रिज के पास, नवजीवन पोस्ट आफिस, अहमदाबाद ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और गुजरात राज्य के अहमदाबाद, गांधी नगर और कैरा जिलो मे अवस्थित स्थान ।
17 क्षेत्रीय प्रबन्धक (पूर्वी क्षेत्र), बैंक आफ बड़ौदा, आयकर कार्यालय के सामने, गांधी ब्रिज के पास, नवजीवन पोस्ट आफिस, अहमदाबाद ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और गुजरात राज्य के बड़ौदा, भड़ौच और पचमहल जिलो मे अवस्थित स्थान ।
18. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), आयकर कार्यालय के सामने, गांधी ब्रिज के पास, नवजीवनपोस्ट आफिस, अहमदाबाद ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और गुजरात राज्य के राजकोट, जूनागढ़, सुरेन्द्र नगर, भाव नगर, कच्छ, जामनगर, अमरेली, साबर काठा, बनास काठा और मेहसाना जिला मे अवस्थित स्थान ।
19. क्षेत्रीय प्रबन्धक (दक्षिणी क्षेत्र), आयकर कार्यालय के सामने, गांधी ब्रिज के पास, नवजीवन पोस्ट आफिस, अहमदाबाद ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और गुजरात राज्य के बलसाड, डाग और सूरत जिलो में अवस्थित स्थान ।
20 क्षेत्रीय प्रबन्धक (बम्बई स्थानीय शाखायें), बैंक आफ बड़ौदा, प्लाट न० 272, फर्स्ट फ्लोर, पीपल्स मोबाइल अस्पताल भवन, डा० एनी बेसेन्ट रोड़, वर्ली. बम्बई ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और ग्रेटर बम्बई मे अवस्थित स्थान ।
21 क्षेत्रीय प्रबन्धक (नागपुर और गोआ क्षेत्र) बैंक आफ बड़ौदा, प्लाट न० 272, फर्स्ट फ्लोर, पीपल्स मोबाइल अस्पताल भवन, डा० एनी बेसेन्ट रोड़, वर्ली, बम्बई ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और महाराष्ट्र राज्य के थाना, नागपुर, अकोला, अमरावती, चन्द्रपुर, मण्डारा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर, परभानी, नान्देड, बुलजना, वर्धा, उस्मानाबाद जिलो तथा संघ शासित क्षेत्र गोआ मे अवस्थित स्थान ।
22. क्षेत्रीय प्रबन्धक (पुणे क्षेत्र), बैंक आफ बड़ौदा, प्लाट नं० 272, फर्स्ट फ्लोर, पीपल्स मोबाइल अस्पताल भवन, डा० एनी बेसन्ट रोड़, वर्ली, बम्बई ।	बैंक आफ बड़ौदा के अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिये गये अथवा अधिगृहीत और महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा, कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सतारा, अहमद नगर, नासिक, धुले, जलगांव और शोलापुर जिलो मे अवस्थित स्थान ।

[सं० 7(9)-बी० ओ० 3/74]

New Delhi, the, 30th March, 1976

S.O. 1369—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column 2 of the said Table.

THE TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
1	2
1. Zonal Manager, Bank of Baroda, 16, Parliament Street, New Delhi.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Union Territories of Delhi and Chandigarh.
2. Zonal Manager, Bank of Baroda, Ruby House, 8, India Exchange Place, Calcutta-1	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the States of West Bengal, Bihar, Assam, Orissa and Meghalaya.
3. Zonal Manager, Bank of Baroda, 4, Park Road, Lucknow.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of Uttar Pradesh.
4. Zonal Manager, Bank of Baroda, 150/A-2, Chordia Mansion, Mount Road, Madras.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu & Union Territory of Pondicherry.
5. Zonal Manager, Bank of Baroda, Opp. Income Tax Office, Near Gandhi Bridge, Navjivan Post Office, Ahmedabad.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of Gujarat.
6. Zonal Manager, Bank of Baroda, Flat No. 272, People's Mobile Hospital Building, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of Maharashtra & Union Territory of Goa.
7. Regional Manager (M.P. & Delhi), Bank of Baroda, 16, Parliament Street, New Delhi.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of M P. and Union Territory of Delhi.
8. Regional Manager (Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir & Union Territory of Chandigarh), Bank of Baroda, 16, Parliament Street, New Delhi-1.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the States of Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir and Union Territory of Chandigarh.
9. Regional Manager Bank of Baroda, Sethi Sadan, 7, Park House, Scheme, Mirza Ismail Road, Jaipur-1.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of Rajasthan.
10. Regional Manager, (West Bangal), Bank of Baroda, Ruby House, 8, India Exchange Place, Calcutta.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of West Bengal.
11. Regional Manager, (Bihar, Orissa, Assam Meghalaya) Bank of Baroda, Ruby House, 8, India Exchange Place, Calcutta.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the States of Bihar, Orissa, Assam & Meghalaya.
12. Regional Manager (Western Dists.) Bank of Baroda, 4, Park Road, Lucknow.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Nainital, Rampur, Bareilly, Pilibhit, Shahajahanpur, Kanpur, Lucknow, Mathura, Aligarh, Meerut, Agra, Dehra Dun, Moradabad, Saharanpur, Muzaffarnagar and Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh.
13. Regional Manager, (Eastern Districts), Bank of Baroda, Post Box No. 198, 4, Park Road, Lucknow.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Rae-Bareli, Faizabad, Pratapgarh, Sultanpur, Fatehpur, Allahabad, Gorakhpur, Varanasi, Lakhimpur Kheri, Sitapur & Jhansi in the State of Uttar Pradesh.
14. Regional Manager, (Tamil Nadu & Pondicherry), Bank of Baroda 150-A/2, Choradia Mansion, Mount Road, Madras-2.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.
15. Regional Manager, (A.P. Karnataka, Kerala), Bank of Baroda, SIET College Avenue, Toynampet, Madras.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the States of Andhra Pradesh Karnataka and Kerala.
16. Regional Manager, (Central Region), Bank of Baroda, Opp. Income Tax Office, Near Gandhi Bridge, Navjivan Post Office, Ahmedabad.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Ahmedabad, Gandhinagar and Kaira in the State of Gujarat.
17. Regional Manager, (Eastern Region), Bank of Baroda, Opp. Income Tax Office, Near Gandhi Bridge, Navjivan Post Office, Ahmedabad-380014.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Baroda, Broach and Panchamahals in the State of Gujarat.
18. Regional Manager, (North West Region), Bank of Baroda, Opp. Income Tax Office, Near Gandhi Bridge, Navjivan Post Office, Ahmedabad.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on bahalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Rajkot, Junagadh, Surendranagar, Bhavnagar, Kutch, Jamnagar, Amreli, Sabarkantha, Banaskantha, & Mehsana in the State of Gujarat.
19. Regional Manager, (Southern Region) Bank of Baroda, Opp. Income Tax Office, Near Gandhi Bridge, Navjivan Post Office, Ahmedabad.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Balsar, Dangs and Surat in the State of Gujarat.
20. Regional Manager, (Bombay Local Branches), Bank of Baroda, Plot No. 272, 1st Floor, People's Mobile Hospital Building, Dr. Annie Besant Rd., Worli, Bombay.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Braoda and situated in Greater Bombay.

21.	Regional Manager, (Nagpur & Goa Region), Bank of Baroda, Plot No. 272, 1st Floor, People's Mobile Hospital Building, Dr. Annie Besant Rd, Worli, Bombay.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Thana, Nagpur, Akola, Amravati, Chandrapur, Bhandara, Yeotmal, Aurangabad, Bhir, Parbhani, Nanded, Buldana, Wardha Osmanabad in the State of Maharashtra and Union Territory of Goa.
22.	Regional Manager, (Pune Region), Bank of Baroda, Plot No. 272, 1st Floor, People's Mobile Hospital, Building, Dr. Annie Besant Rd., Worli, Bombay.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bank of Baroda and situated in the Districts of Kolaba, Kolhapur, Pune, Sangli, Satara, Ahmednagar, Nasik, Dhule, Jalgaon and Sholapur in the State of Maharashtra.

[No. 7(9)-B.O. III/74]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1976

का०आ० 1370.—बैंककारी विनियम, अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ङक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उसमें उल्लिखित निवेश की सीमा को एतद्द्वारा साढ़े सात लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये करती है ।

[सं० 11(40)-बी०ओ० III/75]

New Delhi, the 2nd April, 1976

S.O. 1370.—In exercise of the powers conferred by clause (na) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby increases the investment limit referred to therein from seven and a half lakhs of rupees to ten lakhs of rupees.

[No. 11(40)-B.O. III/75]

का० आ० 1371.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, 6 फरवरी, 1977 तक निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में "दी ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स लि०, नयी दिल्ली" पर लागू नहीं होंगे :

(1) दुकान सं० 405 और 406 तथा

(2) दुकान और घर सं० 420, 421 तथा 422 (दुकानें) और घर सं० 85

जो, बैंक द्वारा बजाजा बजार मेरठ शहर में धृत है ।

[सं० 15(3)-बी० ओ० III/76]

S.O. 1371.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act, shall not apply to the Oriental Bank of Commerce Ltd, New Delhi, in respect of the immovable properties, viz.,

(i) Shop Nos. 405 and 406 and

(ii) Shop-cum-House Nos. 420, 421 and 422 (Shops) and House No. 85,

both held by it at Bazar Bazaza, Meerut City, till the 6th February 1977.

[No. 15 (3)-B.O. III/76]

का० आ० 1372.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 30 मार्च, 1977 तक निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में "दी ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड नई दिल्ली" पर लागू नहीं होंगे :

(1) एक दुमंजली दुकान, सं० 136, बजाजा बाजार, मेरठ शहर

(2) एक दुमंजला मकान सं० 137, मोहल्ला डालमपाड़ा, मेरठ शहर ।

[सं० 15(7)-बी० ओ० III/76]

S.O. 1372.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply, till the 30th March 1977, to the Oriental Bank of Commerce Ltd., New Delhi, in respect of its following immovable properties :

(i) One double storey shop No. 136, Bazar Bazaza, Meerut City.

(ii) One double storey house No. 137, Mohalla Dalampara, Meerut City.

[No. 15(7)-B.O. III/76]

का० आ० 1373.—बैंककारी विनियमन, अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध, "दी ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स, नई दिल्ली" द्वारा 2 जनवरी, 1967 से धृत सुप्रभात इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों के सम्बन्ध में, 1 जनवरी, 1978 तक उक्त बैंक पर लागू नहीं होंगे ।

[सं० 15(10)-बी०ओ० III/76]

मे० भा० उसगांयकर, अवर सचिव

S.O. 1373.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the Oriental Bank of Commerce Ltd., New Delhi, till the 1st January 1978 in respect of the shares of the Suprabhat Engineering Co. Ltd., held by it as pledgee since the 2nd January 1967.

[No. 15(10)-B.O. III/76]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 1374.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दिनांक 6 दिसम्बर, 1972 के विस्कोस स्टेपल रेशा वितरण आदेश, 1972 को 1 अप्रैल 1976 से एतद्द्वारा रद्द करती है ।

[फा० सं० 18011/15/75-टैक्स(5)]

एस० वेणुगोपालन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi the 1st April, 1976

S.O. 1374.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government, hereby rescinds with effect from 1st April, 1976, the Viscose Staple Fibre Distribution Order, 1972 dated the 6th December, 1972.

[F. No. 18011/15/75-Tex(V)]

S. VENUGOPALAN, Dir.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1976

का०आ० 1375—वरिष्ठ भंडार अधिकारी, डी एल डब्ल्यू, वाराणसी के नाम से संयुक्त राज्य अमरीका से इनर कांसल स्नबर का आयात करने के लिए 3,46,300/- रुपए के लिए आयात लाइसेंस संख्या जी/आर 2089223, दिनांक 11-6-73 प्रदान किया गया था । लाइसेंसधारी ने इस कार्यालय से सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रति सीमाशुल्क कार्यालय कलकत्ता में पंजीकृत कराने के पश्चात् तथा कुछ भी प्रयोग में लाए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

इस तर्क के समर्थन में आवेदन ने स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

आधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या जी/आर/2089-223, दिनांक 11-6-73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति आवेदक से खो गई/अस्थानस्थ हो गई है तथा निदेश देता है कि लाइसेंसधारी के नामे में सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए । आयात लाइसेंस संख्या जी/आर/2089223, दिनांक 11-6-73 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या 26 एस/रेलवे/73-74/जी एल एस]

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 27th March, 1976

S.O. 1375.—An Import Licence No. G/R/2089223 dated 11-6-73 for Rs. 3,46,300/- only for the import of inner coil snubber from U.S.A. was issued in favour of Senior Stores Officer, Diesel Locomotive Works, Varanasi. Now the licensee has requested this office for issue of a duplicate Customs Copy of the same on the ground that the original Customs Copy has been lost/misplaced after having been registered with Calcutta Custom House and fully unutilised.

In support of the request the applicant has filed an affidavit on Stamped Paper.

The undersigned is satisfied that the original Customs Copy of import licence No. G/R/2089223 dated 11-6-73 has been lost/misplaced by the applicant and directs that duplicate Customs Copy should be issued in favour of the licensee.

The original Customs Copy of import licence No. G/R/2089223 dated 11-6-73 is hereby cancelled.

[No. 26. S/Rly/73-74/GLS|1183]

आदेश

नई दिल्ली 31 मार्च, 1976

का० आ० 1376—सचिव (एस एंड टी), रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के नाम से जापान से माइक्रोवेव इक्यूपमेंट टेस्टिंग इन्स्ट्रूमेंटस का आयात करने के लिए 5,73,125/- रुपये का सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या जी/जे/3036983, दिनांक 15-6-1972 प्रदान किया गया था । लाइसेंसधारी ने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस कार्यालय को इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रति सीमाशुल्क कार्यालय बम्बई में बिना पंजीकृत कराए तथा कुछ भी उपयोग में लाए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या : जी/जे/ 3036983, दिनांक 15-6-72 की मूल प्रति आवेदक से खो गई/अस्थानस्थ हो गई है तथा निदेश देता है कि लाइसेंसधारी के नाम में सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए ।

सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या : जी/जे/3036983, दिनांक 15-6 1972 की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[सं० 19 एसे/रेलवे/72-73/जी एल एस]

ए० टी० मुखर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक
कृत्य मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 1376—CCP No. G/J/3036983 dated 15-6-1972 for Rs. 5,73,125/- only for the import of Microwave equipment testing instruments from Japan was issued in favour of the Secretary (S&T), Ministry of Railway, Railway Board, New Delhi. Now the license has requested this office for issue of a duplicate CCP on the ground that the original CCP has been lost/misplaced and not registered with Bombay Custom House and fully unutilised.

In support of the request the applicant has filed an affidavit on Stamped Paper.

The undersigned is satisfied that the original CCP No. G/J/3036983 dated 15-6-1972 has been lost/misplaced by the applicant and directs that duplicate CCP should be issued in favour of the licensee.

The original CCP No. G/J/3036983 dated 15-6-1972 is hereby cancelled.

[No. 19-S/Rly/72-73/GLS/478]

A. T. MUKHERJEE, Deputy Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1976

का० आ० 1377.—सर्वश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०, हिमालय हाउस (दूसरी मंजिल), 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को 30,858/- रुपए (तीस हजार आठ सौ अट्ठावन रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या : आई/सी/2070088/आरकेके/76/एच/41-42/सी-जी-2, दिनांक 3-9-1975 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं की गई है तथा बिलकुल भी उपयोग में नहीं लाई गई है ।

2 इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी, दिल्ली के समक्ष विधिवत् शपथ लेते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है । अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9(सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उक्त लाइसेंस संख्या आई/सी/2070088/आर/केके/56/एच/41-42/सीजी-2, दिनांक 3-9-1975 जोकि सर्वश्री इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि०, हिमालय हाउस (दूसरी मंजिल), 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को जारी किया गया था, इसकी मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है ।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० सी जी–2/पी एंड सी/75/75-76/2332]

(अपठनीय)

उप मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1976

S.O. 1377.—M/s. Indian Petrochemicals Corporation Limited, Himalaya House (2nd loor), 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi were granted an Import Licence No. I/C/2070088/R/KK/56/H-41-42|CG. II dated 3-9-1975 for Rs. 30,858/- (Rupees thirty thousand eight hundred fifty eight only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes Copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purpose Copy has not been registered with any Customs Authority and not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filled an affidavit duly sworn in before the Notary, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the power conferred under Sub-section 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-121955 as amended, the said original Customs Purposes Copy of the Licence No. I/C/2070088/R/KK/H/41-42|CG. II dated 3-9-1975 issued to M/s. Indian Petrochemicals Corporation Limited, Himalaya House (2nd floor), 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CG-II/P&C/75/75-76/2332]

Sd/- Illegible.

Deputy Chief Controller

[संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय
(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1976

का० आ० 1378.—अप्रैल/मार्च, 73 तथा अप्रैल-मार्च, 74 की अवधि के लिए सुस्थापित आयातक के लिए आयात व्यापार नियंत्रण क्रम सं० 92 (एन)/5 के अन्तर्गत सर्वश्री फेयर ट्रेडिंग कं० 1228 वकीलपुरा, चाह रहत, दिल्ली के सामान्य मुद्रा क्षेत्र से औजार उपकरण तथा उसके पुर्जे आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या: पी० ई०/1808855 तथा पी० ई 1808856, दिनांक 21-8-74 प्रदान किए गए थे ।

2. पार्टी ने सूचित किया है कि उक्त लाइसेंसों की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां बिना उपयोग में लाए हुए खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उनके रद्द करने के लिए आवेदन किया है । पार्टी ने उनकी मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि भी जारी करने का आवेदन किया है । आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975 के पैरा 320 के अन्तर्गत पार्टी ने अपने उपर्युक्त विवरण के समर्थन में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है ।

3. आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 की धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं पूर्वोक्त मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

4. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975-76 की कंडिका 320(4) के अनुसार आवेदक को 1250/- रुपये के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से पूर्वोक्त लाइसेंसों की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी की जा रही है ।

[फा० सं० 92-5/52/ए एम-74/क्यू एल/सीए एल/(1444)]

डी० पी० माथुर, उप-मुख्य नियंत्रक

कृत्य संयुक्त मुख्य नियंत्रक

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
(Central Licencsing Area)

ORDER

New Delhi, the 24th January 1976

S.O. 1378.—M/s. Fair Trading Co. 1228 Vakil Pura Chah Rahat, Delhi were granted licence No. P/E 1808855 and P/E/1808856 dated 21-8-74 for Rs. 1250/- each on G.A. for import of Instruments, apparatus and appliances and Parts thereof under I.T.C. S. No. 92(N)-V for AM-73 & AM-74 periods an Established Importer.

2. The party have intimated that the Exchange Control Purpose copies of the above said licences has been lost/misplaced without having been utilised at all and have requested for Cancellation thereof. Party have also requested to issue duplicate Exchange Control Purpose copies of the same. The party have filed an affidavit in support of above statement as required vide para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76.

3. In exercise of the Power Conferred on me under Section 9(CC) of Import Trade Control Order 1955 dated 7th December, 1955, I order the Cancellation of the aforesaid Exchange Control Purpose copy of the licence.

4. The applicant is now being issued duplicate Exchange Control Purpose aforesaid licences for Rs. 1250/- p.m. G.A. for utilisation in accordance with the provision of para 320(4) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1975-76.

[F. No. 92-V/52/AM-74/QL/CLA/1444]

D. P. MATHUR, Dy. Chief controller
for Joint Chief Controller

[उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय
(लोहा तथा इस्पात)]

रद्द करने का आदेश

फरीदाबाद, 17 नवम्बर, 1975

का० आ० 1379.—सर्वश्री विन्डेट हिन्द प्रा० लि०, 32, विकासपुर, छठा मील पत्थर, जीटी रोड, गाजियाबाद को अप्रैल-मार्च, 70 अवधि के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत मद, प्राइम औवरोधी इसपात राड के लिए 19,174 रुपये का एक आयात लाइसेंस संख्या: पी०एस०/8564371/सी/एक्स एक्स/42/डी/29-30, दिनांक 29-3-72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के

लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति पारगमन में खो गई है । आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस का 2104 रुपये के लिए आंशिक रूप से उपयोग किया गया था और अब अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की आवश्यकता अप्रयुक्त मूल्य अर्थात् 17070 रुपये के लिए है ।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या: पी०/एस०/8564371, दिनांक 29-3-72 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को रद्द कर आवेदक को 17070 रुपये का उपयोग करने के लिए विषयाधीन आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए ।

[सं० पी/डब्ल्यू-1/ए एम-70/इं एक्स/एयू/यूपी]

के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy. Chief Controller of Import and Exports)
(Iron & Steel)

CANCELLATION ORDER

Faridabad, the 17th November, 1975

S.O. 1379.—M/s. Windet Hind Pvt. Ltd., 32 Chikambarpur, 6th mile stone, G.T. Road, Ghaziabad were granted an import licence No. P/S/8564371/C/XX/42/D/29-30 dated 29-3-72 for the item Prime Stainless Steel Rod for Rs. 19,174/- under G.C.A. for April—March 70 period with the port of registration as Bombay. They have applied for issue of duplicate Exchange Clearance purpose Copy of this licence on the ground that the original E.C.P. copy of the licence has been lost in transit. It is further stated that the original licence was utilized partly for Rs. 2104/- and the duplicate exchange Control Copy is required for the unutilised value of Rs. 17,070/-.

In support of this contention, the applicant has field an affidavit. I am satisfied that the original ECP copy of licence No. P/S/8564371 dated 29-3-72 has been lost and direct that the duplicate ECP copy should be issued to the applicant in cancellation of the Original ECP copy of the import licence in question for utilisation for the value of Rs. 17,070/.

[No. P/W. 1/AM 70/Ex/AU/UP]

R. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller

पेट्रोलियम मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1976

का० आ० 1380.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1631 तारीख 14-4-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

5 GI/76—3.

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डी० एस० एस० डी० ए० से एस० बी० बी० तक पाइपलाइन

राज्य: गुजरात जिला मेहसाना तालुका मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	ए० आर० सेन्टीयर ई०	
जगूदन	97	0	06	00
	96	0	05	50
	102	0	04	00
	92	0	12	00

[सं० 12016/2/75-एल० एंड एल०]

MINISTRY OF PETROLEUM

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 23rd, March, 1976

S. O. 1380—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum SO.No.1631 dated 14-4-75 under sub-section(1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right to User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And Further Whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to this notification ;

Now Therefore in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And Further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline From DS. SDA to SEV
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Jagudan	97	0	06	00
	96	0	05	50
	102	0	04	00
	92	0	12	00

[No. 12016/2/75-L & L]

का० आ० 1381—यत. पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 4642 तारीख 3-10-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार करने अर्जित का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संधको से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बेक्स से बी० डी० जैड० तक उपयोग के अधिकार का अर्जन

राज्य : गुजरात जिला काइरा तालुका मतार

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए० आर० सेन्टीयर ई०	
गोबलेज	394	0	01	75
	398/1	0	06	00
	398/2	0	04	25
	391	0	04	25
	401	0	00	50
	402	0	07	75
	405	0	04	25
	419/2	0	04	75

[सं० 12016/13/75-एल० एंड एल०]

S.O 1381.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum S.O.No. 4642 dated 3-10-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right to User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And Further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Acquistion OF R.O.U. from BEX to bdz

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Goblege	394	0	01	75
	398/1	0	06	00
	398/2	0	04	25
	391	0	04	25
	401	0	00	50
	402	0	07	75
	405	0	04	25
	419/2	0	04	75

[No. 12016/13/75-L & L]

का० आ० 1382—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 5139 तारीख 6-12-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संधकों से मुक्त रूप मे, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : विरामगाम जिला : अहमदाबाद

गांव	सर्वेक्षण नं०	क्षेत्र एक० ए० वर्गमील
विरामगाम	1233	0–12–25
	1231	0–28–90
हंसलपुर सुरेश्वर	55	0–07–35

[सं० 12017/1/75-एल० एंड एल०]

टी० पी० सुब्रह्मण्यिम, अवर सचिव

S.O. 1382.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O.No. 5139 Dated 6-12-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumberances.

SCHEDULE

Taluka : Viramgam Dist : Ahmedabad
Gujarat State

Village	Survey No.	Extent H.A. Sq.M
Viramgam	1233	0-12-25
	1231	0-28-90
HansalPur-Suroshvar	55	0-07-35

[No. 12017/1/75-L & L]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1976

का० आ० 1383.—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (उर्वरक और रसायन विभाग) की अधिसूचना संख्या 24(11)/74-सी० एच० II, तारीख 31-10-75 के साथ प्रकाशित, शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के खंड 11 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निदेश देती है कि उक्त खंड के उपखंड (1) के उपबन्ध केरल राज्य में इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[संख्या एल० 15021(5)/76-सी० एच० II]

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the 27th March, 1976

S.O. 1383.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of Clause 11 of the Molasses Control Order, 1961, as amended by the Molasses Control (Amendment) Order, 1975, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Fertilizers & Chemicals) No. 24(11)/74-Ch.II dated the 31st October, 1975, the Central Government hereby directs that the provisions of sub-clause (1) of the said clause, shall come into force in the State of Kerala with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

[No. L 15021(5)/76-Ch.II]

का० आ० 1384.—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (उर्वरक और रसायन विभाग) की अधिसूचना संख्या 24(11)/74-सी० एच० II, तारीख 31-10-75 के साथ प्रकाशित, शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के खंड 11 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुये, निदेश देती है कि उक्त खंड के उपखंड (1) के उपबन्ध गुजरात राज्य मे इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[संख्या एल० 15021(5)/76-सी० एच० II]

के० पी० श्रीवास्तव, अवर सचिव

S.O. 1384.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of Clause 11 of the Molasses Control Order, 1961, as amended by the Molasses Control (Amendment) Order, 1975, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Fertilizers & Chemicals) No. 24(11)/74-Ch.II dated the 31st October, 1975, the Central Government hereby directs that the provisions of sub-clause (1) of the said clause, shall come into force in the State of Gujarat with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

[No. L-15021(5)/76-Ch II]

K. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का०आ० 1385 —समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम के 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है, वे अब रद्द हो गए है।

अनुसूची

लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंसी के अधीन वस्तु। प्रक्रिया	तत्सम्बंधी भारतीय मानक	रद्द किए जाने की तिथि	रद्द किए जाने का कारण
सीएम/एल-3186 19-10-1972	मेसर्स किसान केमिकल्स, 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट पिंजौर	एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव	IS:1310-1974	1 जनवरी 1976	फर्म के अपने अनुरोध पर।
सीएम/एल-3801 11-4-1974	मेसर्स भंडारी क्रासफील्ड्स प्रा० लि० मगलिया गांव जिला इंदौर	मुर्गियों का दाना (चूजो का दाना आठ हफ्ते से बड़े चूजों का दाना, अंडादायी मुर्गियों का दाना)	IS:1374-1968	16 फरवरी 1976	फर्म का नाम बदल गया है
सीएम/एल-3802 11-4-1974	मेसर्स भंडारी क्रासफील्ड्स प्रा० लि० मगोलिया गाव जिला इन्दौर	पशुओं के लिए संतुलित मिश्रित आहार	IS:2052-1968	16 फरवरी 1976	फर्म का नाम बदल गया है

[सं०एम०डी०डी०/55:-3186]

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

Department of Industrial Development

Indian Standards Institution

New Delhi the 22nd, March, 1976

SO 1385: In pursuance of sub-regulation (4) of the Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended form time to time, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the following licences particulars of which are given below, have been cancelled :

Licence No. and Date	Name and address of the Licensee	Article/Process covered by the licence	Relevant Indian Standard	Date of Cancellation	Reasons for Cancellation
CM/L-3186 19-10-1972	M/s Kisan Chemicals, 3, Industrial Estate, Pinjore.	Endrin EC	IS : 1310-1974	1 Jan 1976	At their own request
CM/L-3801 11-4-1974	M/s Bhandari Crosfield Pvt. Ltd., Mangliagaon Distt. Indore	Poultry Feeds (SPF, GPF, LPF)	IS : 1374-1968	16 Feb 1976	The name of their firm has been changed
CM/L-3802 11-4-1974	M/s Bhandari Crosfield Pvt. Ltd. Mangliagaon, Distt. Indore.	Balanced feed mixtures for cattle	IS : 2052-1968	16 Feb 1976	The name of their firm has been changed

[No. MDD/55 : 3186]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

का०आ० 1386 : समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार और IS: 1984 (भाग 1)-1971 भेषजीय दवाओं (प्रिपेरेशन्स) के लिए कांच की फाइले भाग 1 भोजन की नली के अतिरिक्त दी जाने वाली दवाओं के लिए फाइले (पहला पुनरीक्षण) के प्रकाशन के फलस्वरूप अधिसूचित किया जाता है कि IS:490-1967 टीके की फाइले (पुनरीक्षित) नामक भारतीय मानक जिसके ब्यौरे भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (2) दिनांक 19-8-67 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2789 दिनांक 4-8-1976 के अंतर्गत छपे थे, अब वापस ले लिया गया है और वह रद्द माना जाए।

[संख्या सीएमडी/13:7]

New Delhi, the 25th March, 1976

S.O. 1386: In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time and consequent upon publication of IS : 1984 (Part I)—1971 glass vials for pharmaceutical preparation : Part I vials for parenternal preparations (*first revision*), it is, hereby, notified that IS : 490-1967 vaccine phials (*revised*), details of which were published under notification number S.O. 2789 dated 4-8-1976, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 19-8-1967, has been withdrawn and stands cancelled.

[No. CMD/13:7]

का०आ० 1387 . . समय समय पर सशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है, वे अब रद्द हो गए है और लागू नही रह गए :

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गऐ भारतीय मानक की सख्या और शीर्षक	राजपत्र अधिसूचना की एसओ संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
1	2	3	4
1	IS 2003–1962 कोकोचूर्ण पडे माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1 सितम्बर 1962 में एस ओ संख्या 2996 दिनांक 17 अगस्त, 1962 के अंतर्गत प्रकाशित	यह भारतीय मानक IS:1806-1975 माल्ट मिश्रित दुग्ध आहारों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) के प्रकाशन के कारण रद्द कर दिया गया।
2.	IS : 4405–1967 लौंग चूर्ण की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 20 अप्रैल, 1968 मे एस ओ सख्या 1367 दिनांक 3 अप्रैल, 1968 के अंतर्गत प्रकाशित	यह भारतीय मानक IS:4404–1975 साबुत और पिसी लौंग की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) के प्रकाशन के कारण रद्द कर दिया गया।

[सं० सी०एम०डी०/13 . 7]

S.O. 1387 : In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, it is hereby, notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn :—

SCDEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
1.	IS : 2003-1962 Specification for malted milk food containing cocoa powder	S.O. 2698 dated 17 August 1962 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1 September, 1962	Cancelled in view of publication of IS : 1806-1975 Specification for malted milk foods (first revision)
2.	IS : 4405-1967 Specification for cloves powder	S.O. 1367 dated 3 April, 1968 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 20 April, 1968	Cancelled in view of publication of IS : 4404-1975 specification for cloves whole and ground (first revision)

[No. CMD/13 : 7]

का०आ० 1388 : भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सस्था ने निम्नलिखित मानक चिन्ह निर्धारित किए है जिनकी डिजाइने शाब्दिक विवरण और भारतीय मानको के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है :

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिन्ह उनके आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद सख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
	IS 5515 ISI	सहनन गुणक उपकरण	IS:5515 1969 संहनन गुणक उपकरण की विशिष्टि	भारतीय मानक सस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते है, स्तम्भ (2) मे दिखाई गई शैली और अनुपात मे तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1-2-1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		डब्ल्यू सी और मूत्रालयो मे पानी के लिए प्लास्टिक की फ्लश टंकियां (बिना वाल्व वाली साइफन नुमा)	IS:7231-1974 डब्ल्यू सी और मूत्रालयो में पानी के लिए प्लास्टिक की टंकियो (बिना वाल्व वाली साइफन नुमा) की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते है स्तम्भ (2) मे दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी गई है।	16-2-1976

[सं० सी०एम०डी 13:9]

S. O. 1388.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standard Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :—

SCHEDULE

Sl No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1		Compaction factor apparatus	IS : 5515-1969 Specification for compaction factor apparatus	The monogram of Indian Standard Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1-2-1976
2.		Plastic flushing cisterns (valveless siphonic type) for water closets and urinals	IS : 7231-1974 Specification for plastic flushing cisterns (valveless siphonic type) for water closets and urinals.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in column (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16-2-1976

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 1389.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिन्ह निर्धारित किए है जिनकी डिजाइने शाब्दिक विवरणों और भारतीय मानकों के शीर्षको सहित नीचे अनुसूची में दी गई हैं :

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमो के निमित्त ये मानक चिन्ह उनके आगे दी गई तिथियो से लागू होंगें :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
		100 कि वो अम्पी 11 किवो तक के खुले में उपयोग वाले तीन फेजी वितरण ट्रांस फार्मर	IS:1180-1964-100 कि वो अम्पी 11 किवो तक के खुले में उपयोग वाले तीन फेजी वितरण ट्रांसफार्मरों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक संख्या दी गई है।	26-11-1975

(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)
2.	IS:1970	हाथ से दाबाकर चलने वाले पृष्ठवाही स्प्रेअर; अवाब-धारक	IS:1970 (भाग 1) 1974 हाथ से दाबाकर चलने वाले पृष्ठवाही स्प्रेअर की विशिष्टि भाग 1 दाब न रखने वाले (तीसरा पुन-रीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनो-ग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-05-01
3.	IS:1976	धान निराने के घूर्णक यंत्र	IS:1976-1969 धान निराने के घूर्णन यंत्रों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनो-ग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार गिकया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।	1975-01-01
4.	IS:2870	दाबधारक पृष्ठवाही स्प्रेअर का चार्ज पम्प	IS:2870-1964 दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेअर के चार्ज पम्प की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनो-ग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।	1975-10-16
5	IS:2928	दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेअर	IS:2928-1964 दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेअर की वि-शिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनो-ग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।	1975-10-16
6.	IS:3634	खेतों में बिलों के धूलन यंत्र	IS:3634-1966 खेतों में बिलों के धूलन यंत्रों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनो-ग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।	1975-01-01
7.	IS:7538	खेतों में प्रयुक्त अपकेन्द्रीय पम्पों के लिए तीन फैजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर	IS:7538-1975 खेती में प्रयुक्त अपकेन्द्रीय पम्पों के लिए तीन फैजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनो-ग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जसा डिजाईन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की और भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।	1976-01-01

[सं० सी०एम०एम०डी०/13:9]

S.O. 1389.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Design. of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
1	2	3	4	5	6
1.		Outdoor type three-phase distribution transformers upto and including 100 kVA 11 kV	IS: 1180-1964 Specification for outdoor type three-phase distribution transformers upto and including 100 kVA 11 kV (revised)	The Monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters, 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the Monogram as indicated in the design.	1975-12-16
2.		Hand-operated compression knapsack sprayer; non-pressure-retaining type	IS: 1970 (Part I)-1974 Specification for hand-operated compression knapsack sprayer Part I non-pressure retaining type (third revision)	The Monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the Monogram as indicated in the design.	1975-05-01
3.		Rotary paddy weedors	IS: 1976-1969 Specification for rotary paddy weeders (first revision)	The Monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-01-01
4.		Charge pump for pressure-retaining knapsack sprayer	IS : 2870-1964 Specification for charge pump for pressure-retaining knapsack sprayer	The Monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the Monogram as indicated in the design.	1975-10-16
5.		Pressure-retaining knapsack sprayer	IS: 2928-1964 Specification for pressure-retaining knapsack sprayer	The Monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' , drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-10-16
6.		Dust applicator for burrows	IS: 3634-1966 Specification for dust applicator for burrows	The Monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1975-01-01
7.		Three-phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application	IS: 7538-1975 Specification for three-phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application	The Monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1976-01-01

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 1390—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों के प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होगी .

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	सहनन गुणक उपकरण	IS 5515-1969 सहनन गुणक उपकरण की विशिष्टि	एक उपकरण	रु० 5 00	1976-02-01
2.	डब्ल्यू सी और मूत्रालयों में पानी के लिए प्लास्टिक की फ्लश टंकियां (बिना वाल्व वाली साइफननुमा)	IS 7231-1974 डब्ल्यूसी और मूत्रालयों में पानी के लिए प्लास्टिक की फ्लश टंकियों (बिना वाल्व वाली साईफननुमा की विशिष्टि)	एक फ्लश टंकी	(1)पहली 10,000 इकाइयों के लिए 50 पैसे प्रति इकाई, और (2) शेष इकाइयों के लिए 25 पैसे प्रति इकाई।	1976-02-16

[संख्या सी०एम०डी०/13 10]

S.O.1390.—In pursuance of sub-regulation(3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution(Certification Marks)Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	Compaction factor apparatus	IS: 5515-1969 Specification for compaction factor apparatus	One Piece	Rs. 5.00	1976-02-01
2.	Plastic flushing cisterns (valveless siphonic type) for water closets and urinals	IS: 7231-1974 Specification for plastic flushing cisterns (valveless siphonic type) for water closets and urinals	One Flushing cistern	(i) 50 Paise per unit for the first 10,000 units; and (ii) 25 Paise per unit for the remaining units	1976-02-16

[No. CMD/13:10]

का०आ० 1391.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों के प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और ये फीसे प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होंगी .

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1	100 कि वो अम्पी 11 कि वो तक के खुले में उपयोग वाले तीन फेजी वितरण ट्रांसफार्मर	IS:1180-1964 100 कि वो अम्पी 11 कि वो तक के खुले में उपयोग वाले तीन फेजी वितरण ट्रांसफार्मरों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1 कि वो	5 पैसे	1975-12-16

1	2	3	4	5	6
2.	हाथ से दबाकर चलने वाले पृष्ठवाही स्प्रेयर, दाबधारक	IS 1970 (भाग 1)-1974 हाथ से दबाकर चलने वाले पृष्ठवाही स्प्रेयर की विशिष्टि भाग 1 दाब म रखने वाले (तीसरा पुनरीक्षण)	एक स्प्रेयर	रु० 1.50	1975-05-01
3	धान निराने के घूर्णन यंत्र	IS. 1976-1969 धान निराने के घूर्णन यंत्रों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक धान निराने का यंत्र	50 पैसे	1975-01-01
4.	दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेयर का चार्ज पम्प	IS:2870-1964 दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेयर के चार्ज पम्प की विशिष्टि	एक चार्ज पम्प	रु० 2.00	1975-10-16
5	दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेयर	IS:2928-1964 दाब धारक पृष्ठवाही स्प्रेयर की विशिष्टि	एक पृष्ठवाही स्प्रेयर	रु० 2 00	1975-10-16
6	खेतो में बिलो के धूलन यंत्र	IS:3634-1966 खेतों में बिलो के धूलन यंत्रों की विशिष्टि	एक धूलन यंत्र	50 पैसे	1975-01-01
7.	खेतों में प्रयुक्त अपकेन्द्री पम्पों के लिए तीन फेजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर	IS:7538-1975 खेतो में प्रयुक्त अपकेन्द्री पम्पों के लिए तीन फेजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर की विशिष्टि	1 किवो	(1) 20,000 और इससे कम इकाइयों के लिए 20 पैसे प्रति इकाई। (2) अगली 40,000 इकाइयों के लिए 10 पैसे प्रति इकाई (3) इससे अगली 40,000 इकाइयो के लिए 5 पैसे प्रति इकाई, और (4) 100,000 इकाइयों से ऊपर के लिए 2 पैसे प्रति इकाई	1976-01-01

[सं० सी० एम० डी०/13:10]
ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S. O. 1391.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of whichare given in the Schedule hereto annexed have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevent Indian Standard	Unit	Marking fee per Unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	Outdoor type three-phase distribution transformers upto and including 100 kVA 11 kV	IS: 1180-1964 Specification for outdoor type three-phase distribution transformers upto and including 100 kVA 11 kV (revised)	1 KVA	5 Paise	1975-12-16

1	2	3	4	5	6	7
2.	Hand-operated compression knapsack sprayer; non-pressure retaining type	IS: 1970 (Pt. I)-1974 Specification for hand-operated compression knapsack sprayer Part I non-pressure retaining type (third revision)	One sprayer	Rs. 1.50		1975-05-01
3.	Rotary paddy weeders	IS: 1976-1969 Specification for rotary paddy weeders (first revision)	One paddy weeders	50 Paise		1975-01-01
4.	Charge pump for pressure-retaining knapsack sprayer	IS: 2870-1964 Specification for charge pump for pressure-retaining knapsack sprayer	One charge pump	Rs. 2.00		1975-10-16
5	Pressure-retaining knapsack sprayer	IS: 2928-1964 Specification for pressure-retaining knapsack sprayer	One knapsack sprayer	Rs. 2.00		1975-10-16
6.	Dust applicator for burrows	IS: 3634-1966 Specification for dust applicator for burrows	One dust applicator	50 Paise		1975-01-01
7.	Three-phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application	IS: 7538-1975 Specification for three-phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application	1 kW	(i) 20 Paise per unit for the first 20 000 units or less; (ii) 10 Paise per unit for the next 40 000 units; (iii) 5 Paise per unit for the next 40 000 units; and (iv) 2 Paise per unit beyond 1 00 000 units.		1976-01-01

[No. CMD/13:10]
A.B. RAO Dy. Dir. Gen.

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1976

का० आ० 1392—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन अहमदाबाद काटन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, अहमदाबाद द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित मे और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे मे, 16 अप्रैल, 1976 से 15 अप्रैल, 1977 (जिस मे ये दोनो दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाये ।

[संख्या 12(5)-आई०टी०/76]

Department of Civil Supplies & Corporation

New Delhi, the 17th March, 1976

S.O. 1392.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Ahmedabad Cotton Merchants' Association, Ahmedabad, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 16th April, 1976 to the 15th April, 1977 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(5)-IT/76]

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

का० आ० 1393.—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन बम्बई आयल सीड्स एण्ड आयलस एक्सचेंज लि० बम्बई मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित मे और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त एक्सचेंज को मूंगफली के तेल की अग्रिम संविदाओं के बारे मे, 25 अप्रैल, 1976 से 24 अप्रैल, 1977 (जिसमे ये दोनो दिन भी सम्मिलित है) को एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशो का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाये ।

[सं०12(6)-आई०टी०/76]

New Delhi, the 20th March, 1976

S.O. 1393.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Bombay Oilseeds and Oils Exchange Limited, Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 25th April, 1976 to the 24th April, 1977 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundnut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(6)-IT/76]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1975

का० आ० 1394.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल इण्डिया काटन एसोसिएशन लि०, उज्जैन द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त एसोसिएशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 16 अप्रैल, 1976 से 15 अप्रैल, 1977 (जिसमे ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाये।

[संख्या 12(7)-आई०टी०/76]

बी० एन० लाल, अवर सचिव।

New Delhi, the 6th April, 1976

S.O.1394.—The Central Government, having considered in consultation the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Secion 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Cotton, Association Ltd; Ujjain and being saisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by the Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 16th April, 1976 to the 15th April, 1977 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Merkets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/76]

B. N. LALL, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 1395.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 12 सितम्बर, 1975 में पृष्ठ 2056 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 506 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 1975 में पंक्ति 6 में "29 मई, 1969" के स्थान पर "29 मई, 1967" पढ़ें।

[सं० 19(29)/75-सी ई० एल०]

एस० आर० ए० रिजवी, उप सचिव।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st April, 1976

S.O. 1395.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 506(E), dated the 12th September, 1975 published at page 2056 of the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 12th September, 1975, in line 5, for "29th May, 1969" read "29th May, 1967."

[No. 19(29)/75-CEL]

S. R. A. RIZVI, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1976

का० आ० 1396.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में 27 दिसम्बर, 1975 को पृष्ठ 4381 पर का० आ० 5381 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० पी 16022/6/75-पी एच (डी और एम एस) तारीख 12 दिसम्बर, 1975 में "15 दिसम्बर 1975" के स्थान पर, जहां कहीं भी आया हो "26 दिसम्बर, 1975" पढ़ें।

[सं० पी० 16022/6/75-पी एच (डी और एम एस)]

रमेश बहादुर, अवर सचिव।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th March, 1976

S.O. 1396.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Planning (Department of Health), No. P. 16022/6/75-PH(D&MS), dated the 12th December, 1975, published in the Gazette of India,

Part II, Section 3, Sub-section (ii), as S.O. No. 5381, dated the 27th December, 1975, at page 4381, **for** "15th December, 1975", wherever occurring, read "26th December, 1975".

[No. P 16022/6/75-PII (D&MS)]

RAMESH BAHADURI, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976

का० आ० 1397.—इस विभाग के तारीख 7 अगस्त, 1974 के आदेश संख्या 52/21/68-एफ० सी० 3(पू० जो०)/खण्ड-4 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएँ :—

आदेश में क्रम संख्या	की जाने वाली शुद्धि
45	स्तम्भ 3 में "प्रधूमन सहायक" के स्थान पर 'तकनीकी सहायक पढ़ें ।
61	स्तम्भ 4 में "कार्यालय अधीक्षक" के स्थान पर "सहायक निदेशक" पढ़ें।
128	स्तम्भ 2 में "श्री एस० के० चौधरी के स्थान पर "श्री सुनील कुमार राय चौधरी" पढ़ें ।

[सं० 52/14/74-एफ० सी० 3 (खंड 3)]

डी० कृष्णामूर्ति, उप सचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th March, 1976

S.O. 1397.—In this Department order No. 52/21/68-FC-III(EZ)/Vol. IV dated 7.8.1974, the following corrections shall be carried out :—

Sl. No. in the Order	Correction to be carried out
45	For the words "Fumigation Assistant" in col. 3, read "Technical Assistant"
61	Read "Assistant Director" instead of "Office Superindent" in col. 4
128	For the words "Shri S. K. Choudhury" in col. 2 read "Shri Sunil Kumar Roy Choudhury".

[No. 52/14/74-FC-III (Vol. III)]

D. KRISHNAMURTHI, Dy. Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1976

का० आ० 1398.—वन्य प्राणि क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास के के निरीक्षक श्री एन० वैद्यनाथन, को एतद्द्वारा वन्य प्राणि(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 की उपधारा (2) तथा (6) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के अलावा वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है ।

[संख्या जे० 13011/5/76-एफ० डी० (डब्ल्यू० एल० एफ०)]

एस० ए० शाह, निदेशक

(Department of Agriculture)

New Delhi the 30th March, 1976

S.O. 1398.—Shri N Vaidhyanathan, Inspector, Wild Life Regional Office, Madras is hereby authorised to exercise powers under Section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, except the powers provided under Sub-Section (2) and (6) of the said section of the Act.

[No. J-13011/5/76-FD (WLF)]

S. A. SHAH, Director

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 1399—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मधु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1970 में संशोधन करना चाहती है । प्रस्तावित संशोधनों का निम्न लिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाए, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिष्टि विधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगें केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

1 इन नियमो का नाम मधुश्रेणीकरण और और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1976 है ।

2. मधु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1970 में,—

(1) नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निदेशित रीति में निम्नलिखित विशिष्टियां आधान पर स्पष्ट रूप से चिह्नांकित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) पैकर का नाम;

(ख) लाट संख्या, जिससे मधु का सम्बन्ध है;

(ग) पैकिंग की तारीख और स्थान;

(घ) शुद्ध भार; और

(ङ) समाप्ति की तारीख ।"

(ii) अनुसूची 1 में,—

(क) श्रेणी अभिधान "श्रेणी क" के सामने, स्तम्भ 5 में, प्रविष्टि "8" के स्थान पर, प्रविष्टि "5" रखी जाएगी;

(ख) श्रेणी अभिधान मानक के समाने,—

(i) स्तम्भ 5 मे, प्रविष्टि "10" के स्थान पर, प्रविष्टि "5' रखी जाएगी,

(ii) स्तम्भ 8 मे, प्रविष्टि "60" के स्थान पर, प्रविष्टि "65" रखी जाएगी ।

[सख्या 13/10/75-ए० एम०]

आर० एन० बक्शी, अवर सचिव

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 1st April, 1976

S.O. 1399.—The following draft rules to amend Honey Grading and Marking Rules, 1970, which the Central Government proposes to make in exercise of the power conferred under section 3 of the Agriculture Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette, in which this notification was published are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect of the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called Honey Grading and Marking (Amendment) Rules, 1976

2. In the Honey Grading and Marking Rules, 1970,—

(1) in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly marked on the container in a manner directed by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, namely :—

(a) Name of the packer;

(b) Lot number to which honey pertains;

(c) Date and Place of packing;

(d) Net weight; and

(e) Date of expiry".

(ii) in Schedule-I,—

(a) against grade designation 'Grade A', in column 5 for the entry "8", the entry "5" shall be substituted,

(b) against grade designation 'Standard',—

(i) in column 5, for the entry "10", the entry "5" shall be substituted;

(ii) in column 8, for the entry "60", the entry "65" shall be substituted.

[No. 13/10/75-AM]

R. N. BAKSHI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1976

का. आ. 1400.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना स. टी.सी 3/3036/58/ अधिसूचना, तारीख 28 अगस्त, 1958 के साथ प्रकाशित रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये 1 मई, 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) नियम, 1958 के नियम 6 में, "माल वैगनों पर विलम्ब-शुल्क", शीर्षक के नीचे की सारणी में, स्तंभ 3 के अन्तर्गत मद (1) और (2) में से प्रत्येक के सामने "वनस्पति तेल टैंक वैगनों के लिए, सभी दिनों के लिए 60 पैसे". शब्दों और अंकों के स्थान पर "वनस्पति तेल टैंक वैगनों के लिए 60 पैसे प्रथम दिन के लिए, 1.00 रुपया, द्वितीय दिन के लिए और 2.00 रुपए तृतीय और उसके पश्चात के लिए". अंक शब्द और अक्षर रखे जायेंगे ।

[सं. टी.सी. आई. 1/203/75/2]

ए. एल. गुप्ता, सचिव, पदेन् संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 22nd March, 1976

S.O. 1400.—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. TCIII/3036/58-notification, dated the 28th August, 1958, namely :—

1. (1) Thesse rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the first day of May, 1976.

2. In rule 6 of the Railways (Warehousing and Wharfage Rules, 1958, in the table appearing under the heading "Demurrage on goods wagons", against each of the items (i) and (ii) under column 1, under column 3, for the figures and words "60 paise for all days for vegetable oil tank wagons", the figures, words and letters "60 paise for the first day, Re 1.00 for the second day, and Rs. 2.00 for the third day and thereafter for vegetable oil tank wagons" shall be substituted.

[No TCI/203/75/2]

A. L. GUPTA, Secy. ex officio Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1976

का० आ० 1401.—मूल नियम के नियम 56 के खण्ड (ञ) (ii) के प्रदत्त द्वारा अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के सहायक प्रादेशिक अधिकारी श्री डी० रामलिंगम को 19 दिसम्बर, 1975 के उपरान्ह मे सेवा-निवृत्त करते हैं ।

[फाइल सख्या 2/2/76-एफ (सी)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd March, 1976

S.O. 1401.—The President is pleased to retire in terms of Clause (j)(i) of Rules 56 of the Fundamental Rules, Shri D. Ramalingam, Assistant Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras with effect from the afternoon of 19th December, 1975.

[F. No. 2/2/76-F(C)]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का० आ० 1402 —चलचित्र (सेंसर) नियम, 1958 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि निम्नलिखित सदस्य 31 मार्च, 1976 (अपराह्न) से केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य नहीं रहेंगे :—

1. कुमारी कुरतउलऐन हैदर
2. श्री अनिल धारकर

[फा० सं० 2/24/75-एफ (सी)]

एम० घोष, उप सचिव

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 1402.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952, read with sub-section (1) of Rule 4 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby directs that the following persons shall cease to be members of the Central Board of Film Censors with effect from 31st March, 1976 (Afternoon):—

1. Miss Qurratulain Hyder
2. Shri Anil Dharker

[F. No. 2/24/75-FC]

S. GHOSE, Dy.. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 1403 —स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 431 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने मामा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-7/76-पी० ए० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 1st April, 1976

S.O. 1403.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Nabha Telephone Exchange, N.W. Circle.

[No. 5-7/76-PHB.]

नई दिल्ली 2 अप्रैल, 1976

का० आ० 1404.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बारगढ़ टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-5-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-15/76-पी० एच० बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी०एच०बी)

New Delhi, the 2nd April, 1976

S.O. 1404.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-5-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Bargarh Telephone Exchange, Orissa Circle.

[No. 5-15/76-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Dir. Gnl. (PHB)

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 1405.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एलेक्स मिल्लर (शिप चान्डलर्स) (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स एलेक्स मिल्लर (शिप चान्डलर्स) (प्राईवेट) लिमिटेड कलकत्ता द्वारा नियोजित नैमित्तिक गियर हस्तन श्रमिकों की निम्नलिखित मांगे न्यायोचित हैं और सम्बन्धित कर्मकार उन के हकदार है? यदि हां, तो किस तारीख से और किस दर/मात्रा से?

मांगे

1. कलकत्ता डाक श्रमिक बोर्ड के अधीन जनरल पूल मजदूरों के समान दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान।
2. प्रतिव्यक्ति 2 रुपये प्रतिदिन की दर से हाजिरी भत्ता।
3. प्रतिमास न्यूनतम 21 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी की स्वीकृति

4. मजदूरी सहित साप्ताहिक विश्राम दिवस की स्वीकृति ।

5. कलकत्ता डाक श्रमिक बोर्ड द्वारा स्वीकृति के आधार पर छुट्टी सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तरण ।

6 वर्दियों की पूर्ति ।

[सं० एल०-32011(22)/75-डी० 4 (ए)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 17th January, 1976

S.O. 1405.—Whereas he Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Alex Miller (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the following demands of the casual gear handling workers employed by Messrs Alex Millers (Ship Chandlers) (Private) Limited, Calcutta, are justified and the workman concerned are entitled to the same ? If so, from what date and at what rate/scale ?

DEMANDS

1. Payment of daily rate of wages at par with General Purpose Mazdoors under the Calcutta Dock Labour Board.
2. Attendance allowance at the rate of Rs. 2/- per head per day.
3. Grant of 21 days' minimum guaranteed wage per month.
4. Grant of weekly day of rest with wages.
5. Extension of leave facilities on the lines allowed by the Calcutta Dock Labour Board.
6. Supply of uniforms.

[No. L-32011(22)/75-D IV (A)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1976

का० आ० 1406.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर काम्पलेक्स की मोसाबनी माईन्स, डाकघर मोसाबनी माईन्स के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 3) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर काम्पलेक्स की मोसाबनी माईन्स, डाकघर मोसाबनी माइन्स, जिला सिंह भूम के प्रबन्धतंत्र की, एक्स-बी संख्या 8029, भूतपूर्व-उत्स्फोटक (एक्स ब्लास्टर), सुर्दा खान श्री उदयनाथ महापात्रा को 22 अगस्त, 1972 से पदच्युत करने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-43012(9)/75-डी-4(बी)]

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1976

S.O. 1406.—Whereas the Central Government is of a opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni Mines and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mostaboni Mines, District Singhbhum in dismissing Shri Udyanath Mahapatra, Ex-B. No. 8029, Ex-Blaster, Surda Mine with effect from the 22nd August, 1972 was justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-43012(9)/75-D. IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

का० आ० 1407.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की मोसाबोनी खान डाकघर मोसाबोनी खान, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त

अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (सं० 3) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की मोसाबोनी खान, डाकघर मोसाबोनी खान, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री जे० मिश्र और एन० के० शुक्ला, भूतपूर्व रेजाओं को पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल० 43012/3/75-डी० 4(बी०)]

ORDER

New Delhi, the 20th February, 1976

S.O. 1407.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, (No. 3) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Messrs Hindustan Copper Limited Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum in dismissing Sarva Shri J. Misra and N. K. Shukla, Ex-Muckers, was justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L. 43012/3/75/D. IV(B)]

आदेश

का० आ० 1408.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कान्तिलाल एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मारगाओ (गोवा) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स एम० कान्तिलाल एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मारगाओ (गोवा) के प्रबन्धतंत्र की उनकी सकोरिया आयरन और माईन के भारसाधक श्री गुरू पै अरवोदकर को 23-10-1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-26012(2)/76-डी० 4(बी)]

ORDER

S.O. 1408.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs S. Kantilal and Company (Private) Limited, Margao (Goa) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial, (No. 2), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs S. Kantilal and Company (Private) Limited, Margao (Goa), in dismissinf Shri Guru Pai Arvodkar, Garage Incharge of their Sancoria Iron Ore Mine, with effect from 23-10-1975, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-26012(2)/76-D-IV(B)]

आदेश

का० आ० 1409.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एस० आर० पुसालकर एण्ड कं०, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स एस० आर० पुसालकर एण्ड कम्पनी, मुम्बई के प्रबंधतंत्र की, लेखा वर्ष 1972-73 के लिए 11.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[संख्या एल०-31011(1)/76-डी०-4(ए)]

ORDER

S.O. 1409.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs S. R. Pusalkar and Company, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs S. R. Pusalkar and Company, Bombay in paying bonus at the rate of 11.33 per cent for the accounting year 1972-73 is justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

[No. L-31011(1)/76-D.IV(A)]

New Delhi, the 30th March, 1976

S.O. 1410.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Dunnage Wood and Scrap Dealers Association, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th March, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT :

JUSTICE E. K. MOIDU....PRESIDING OFFICER

Reference No. 72 of 1975 :

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Dunnage Wood and Scrap Dealers Association, Calcutta,

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers } ABSENT
On behalf of Workmen }

State : West Bengal Industry : Port & Dock

AWARD

This reference arises out of Order No. L-32012/12/75-D-IV(A), dated 21st November, 1975 of the Ministry of Labour, Government of India under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The reference reads :

"Whether the action of the management of Messrs Dunnage Wood and Scrap Dealers Association, Calcutta in terminating the services of Shri Bacha Lal Choudhury, Watchman with effect from the 1st February, 1975 is justified ? If not, to what relief is he entitled ,"

This reference came up for final hearing on 17-3-1976. Though summons was received by both parties, they did not file any written statement. The final date of hearing was also communicated to them and yet they did not turn up on 17-3-1976. It was posted to 18-3-1976 and again to 19-3-1976 The parties were still absent.

3. In the absence of either side it was not possible to proceed with the hearing of the reference. In the result, the reference is rejected as unprosecuted.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

[No. L-32012(12)/75/D.IV(A)]

Dated, Calcutta,
The 19th March, 1976. NAND LAL, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1976

आदेश

का० आ० 1411.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोल माइन्स अथारिटि लिमिटेड की हरियाजाम कोलियरी, डाकघर निसाचिट्टी, धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय (सं० 3), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कोल माईन्स अथारिटी लिमिटेड की हरियाजाम कोलियरी, डाकघर निसाचिट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री बारासिंह चवान, पर्यवेक्षक को विभागीय श्रमिकों का कमिशन के आधार पर पर्यवेक्षण करने के लिए रखने और 30 जनवरी, 1973 से उसकी सेवाओं में उसे नियमित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-20012/103/75-डी०-III(ए०)]

ORDER

New Delhi, the 20th January, 1976

S.O. 1411.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Hariajam Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachati, Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum-labour-Court (No. 3), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCEDULE

Whether the action of the management of Hariajam Colliery of Coal Mines Authority Limited, Post Office Nirsachati District Dhanbad in keeping Shri Dara Singh Chawan, Supervisor to supervise departmental workers on commission basis and not regularising him in his services with effect from 30th January, 1973 is justified ? If not, to what relief is he entitled ?

[No. L-20012/103/75-D.III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1976

का० आ० 1412.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की साउथ तिसरा कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2 को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स कोकिंग कोल लिमिटेड की साउथ तिसरा कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र का, श्री श्याम लाल शर्मा, खजांची को 17-9-1973 से रोजगार देने से इनकार करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल-20012/148/75-डी०-3(ए०)]

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1976

S.O. 1412.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of South Tisra Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas Jeenagora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-Cum Labour Court No. 2 constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of South Tisra Colliery of Messrs Bhat Coking Coal Limited, P. O. Khas Jeenagora, District Dhanbad, is justified in refusing employment with effect from 17-9-1973 to Shri Shyam Lal Sharma, Cashier? If not to what relief he is entitled ?

[No. L-20012/148/75-D-III-A]

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1976

का० आ० 1413.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नार्थ तिआरा कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा (जिला धनबाद) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नार्थ तिआरा कोलियरी डाकघर खास जीनागोरा (जिला धनबाद) के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री (1) महेन्द्र रेवानी और (2) तारा मल्लाह मजदूरों को नियमित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एल०-20012/162/75-डी०-III (ए०)]

ORDER

New Delhi, the 22nd January 1976

S.O. 1413.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of North Tiara Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P. O. Khas Jeenagora (District Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Cum-Labour Court No. 3 Dhanbad constituted under section 7-A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of North Tiara Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas Jeenagora (District Dhanbad) in not regularising of S/Shri (1) Mahendra Rewani and (2) Tara Mallah Mazdoors, is justified , If not, to what relief are the said workmen entitled and from which date ?

[No. L-20012/162/75-D-III(A)]

आदेश

का० आ० 1414.—केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० की नार्थ तिआरा कोलियरी, डाकघर झरिया (जिला धनबाद) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम

की धारा 7-क के अधीन गठित, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय सं० 3, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नार्थ तिआरा कोलियरी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की 3-5-1975 से निम्नलिखित वैगन लोडरों को काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है?

1. श्री योगिन्द्रा भुइयाँ
2. श्री बासदेव भुइयाँ
3. श्री महाबीर भुइयाँ
4. श्री हरदयाल भुइयाँ
5. श्री मुडा भुइयाँ
6. श्री लच्छवा मल्लाह
7. श्री शिवनन्द मल्लाह
8. श्री सोनिया भुइयाँ

यदि नहीं, तो वे किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एल०-20012/168/75-डी०-(III)/ए)]

ORDER

S.O. 1414.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of North Tiara Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jharia (Dist Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considered it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court No. 3 constituted under section 7-A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of North Tiara Colliery of Messrs Bharat Coking coal Limited, P.O. Jharia, District Dhanbad in stopping from work the following Wagon Loaders with effect from 3-5-1975 is justified ?

1. Shri Yogindra Bhuian
2. Shri Basdeo Bhuia
3. Shri Mahabir Bhula.
4. Shri Hardayal Bhuia.
5. Shri Munda Bhuia.
6. Shri Lachwa Mallah.
7. Shri Sheonanandan Mallah.
8. Shri Sonia Bhuia.

If not to what relief they are entitled ?

[No. L-20012/168/75-D-III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1976

का० आ० 1415.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लोयाबाद कोलियरी, डाकघर बांसजीरा, धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लोयाबाद कोलियरी, डाकघर बांसजीरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री आर० के० प्रसाद, लैम्प केबिन प्रभारी को 19 नवम्बर, 1973 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल 20012/110/75 डी-3/ए)

New Delhi, the 3rd February, 1976

S.O. 1415.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Cum-Labour Court No. 2 constituted under section 7-A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Leyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd; Post Office Bansjora, District Dhanbad in dismissing Shri R. K. Prasad, Lamp Cabin Incharge with effect from the 19th November, 1973 is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?

[No. L-20012/110/75-D-III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

का० आ० 1416.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० की नुवखर्की कोलियरी, डाकघर नुवखर्की, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नुदखर्की कोलियरी डाकघर नुदखर्की, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री साहदेव पांडे, रात्रि रक्षक को 19 दिसम्बर, 1974 से पदच्युत करने की कारवाई न्यायायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 20012/145/75 डी०-III]

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1976

S.O. 1416.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nudkhurkee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Nudkhurkee, Dist. Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Indusrtial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Dhanbad constituted under section 7-A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Nudkhurkee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Nudkhurkee, Dist. Dhanbad in dismissing Shri Suhdeo Pandey, Night Guard with effect from 19th December, 1974 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ? "

[No. L-20012/145/75-D-III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

का० आ० 1417.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बी० सी० सी० लि० की सेन्द्रा बांसजोरा कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केंद्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं० 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स बी० सी० सी० लि० की सेन्द्रा बांसजोरा कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री राम बारन साव, सी० सी० एम० ड्राईवर को नवम्बर, 1974 से केन्द्रीय कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार प्रवर्ग 6 में सैनात करने से इन्कार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोषका हकदार है और किस तारीख से ?"

[सं० एल०-20012/150/75-डी० III(ए)]

ORDER

New Delhi, the 20th February, 1976

S.O. 1417.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., P.O. Bansjora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sendra Colliery of M/s. B.C.C. Ltd., P.O. Bansjora, District Dhanbad is justified in refusing to place Shri Rambaran Saw, C.C.M. Driver in Category VI as per Central Coal Wage Board Recommendations, from November, 1974 ? If to what relief the said workman is entitled and from which date ?"

[No. L-20012/150/75-D-III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1976

का० आ० 1418.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की फुलारी टोड कोलियरी, डाकघर खारोखारी (धनबाद) के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की फ्लारी टोड कोलियरी डाकघर खारखारी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री हरेन्द्र-नाथ कंवर, ट्रैम्मर को 23 मार्च, 1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-20012/141/75-डी०-III(ए०)]

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1976

S.O. 1418.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Phularitand Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Kharkharee (Dhanbad) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2 Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Phularitand Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Kharkharee, Dist. Dhanbad in dismissing Shri Harendar Nath Kunwar, Trammer with effect from 23rd March, 1975 is jutified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

[No. L-20012/141/75-D-III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1976

का० आ० 1419.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दामोदा कोलियरी, डाकघर कर्मटांड गिरिडिह के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दामोदा कोलियरी, डाकघर कर्मटांड बरास्ता मोहुदा (जिला गिरिडिह) के प्रबन्धतंत्र की श्री एन० डी० शर्मा को मुख्य फिटर (प्रवर्ग 6) न बनाने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और किस तारीख से ?"

[सं० एल०-20012/193/75-डी०-III(ए०)]

आर० पी० नरूला, अवर सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 2nd April, 1976

S.O. 1419.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Limited, P. O. Karamatand Giridih and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour-Court No. 2, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Karmatand *via* Mohunda (Dist. Giridih) in not placing Shri N. D. Sharma as Head Fitter (Category VI) is justified ? If not to what relief the workman is entitled and from what date ?"

[No. L-20012/193/75-D-III(A)]

R. P. NARULA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1976

का० आ० 1420.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संगानेरी गेट शाखा, जयपुर की पहली अगस्त, 1974 से श्री गोपाल सिंह, गोदाम दरबान की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित और बैध है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/141/75-डी०-II(ए०)]

New Delhi the 21st January, 1976

S.O. 1420.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding officer, with headquarters at Jaipur and refers the said disputes for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the State Bank of India Sanganari Gate Branch, Jaipur in terminating the services of Shri Gopal Singh, Godown-Darban, with effect from the Ist August, 1974 is justified and legal ? If not to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/141/75-D-II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1976

का० आ० 1421.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अत , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, क्षेत्र 6, संसद भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र का श्रीमती इन्दु शर्मा, अस्थायी रोकडिया की 13 फरवरी, 1973 से सेवाएं समाप्त करना न्यायायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष की हकदार है ?

[सं० एल० 12012/148/75-डी० 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 28th January, 1976

S.O. 1421.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their Workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the State Bank of India, Region VI, Parliament House, New Delhi is justified in terminating the services of Shrimati Indu Sharma, temporary Cashier, with effect from the 13th February, 1973 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/148/75-D-II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 19 फरवरी, 1976

का० आ० 1422.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र द्वारा 23 जुलाई, 1975 से श्री जी० मल्लेश्वर राव, संदेश वाहक की सेवा समाप्त करना अन्यायोचित है या वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25 ञ के उपबन्धों का अनुपालन न करके छंटनी का मामला है ? किसी भी मामले में उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल० 120 12/169/75-डी० 2/ए०]

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 1422.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workman in respect of the matter spefiified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narsing Roa shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the termination of service with effect from the 23rd July, 1975 of Shri G. Maleswar Rao, Messenger by the management of the State Bank of India, Hyderabad is justified or is a case of retrenchment without complying with the provisions of section 25 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ? in either case, to what relief is the said workmen entitled ?

[No. L. 12012/169/75-D-II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

का० आ० 1423.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की शिलांग शाखा के श्री जनार्दन शर्मा, मुख्य कोषाध्यक्ष को उक्त बैंक के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, गौहाटी द्वारा सेवा से पदच्युत करना न्यायोचित है यदि नहीं तो, उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 13012/175/75-डी-2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1976

S.O. 1423.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the dismissal from service of Shri Janardan Sarma, Head Cashier, Shillong Branch of the Central Bank of India by the Assistant Zonal Manager of the said Bank, Gauhati is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/175/75-D-II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976

का० आ० 1424.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० यू० शाह होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक, बम्बई के प्रबन्धतंत्र की श्री सी० के० पटेल, विशेष सहायक को उक्त बैंक की कादी शाखा से नडियाड शाखा में स्थानान्तरित करने और उनको उक्त बैंक की कादी शाखा में लेखपाल के रूप में पदोन्नति देने से इनकार करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/113/75-डी० 2(ए)]

आर० कुंजीथापादम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1976

S.O. 1424.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. U. Shah, shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahemdabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Punjab National Bank, Bombay in transferring Shri C. K. Patel, special Assistant, from Kadi Branch to Nadiad Branch of the said Bank and in denying him promotion as Accountant at Kadi Branch of the said Bank is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/113/75-D-II(A)]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1976

का० आ० 1425.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन, सामेम-5 के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पाला-नियाप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया मैगनेसाईट कारपोरेशन, सालेम-5 के प्रबन्धतंत्र का, श्री० सी० मायिलवेलान, मजदूर की सेवाओं को 26-4-75 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-29011/110/75-डी-III (बी)]

ORDER

New Delhi, the 29th January, 1976

S.O. 1425.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer in relation to the management of Messrs. Dalmia Magnesite Corporation, Salem-5 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palamappan shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Messrs. Dalmia Magnesite Corporation, Salem-5, is justified in terminating the services of Shri C. Mayilvelan, Mazdoor, with effect from 26-4-75 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-29011/110/75-D-III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1976

का० आ० 1426.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, रामागुंडम प्रभाग, गोदावरी खनी (डाकघर) करीमनगर (जिला आन्ध्रप्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, रामागुंडम प्रभाग II, गोदावरी, खनी डाकघर, करीमनगर जिला (आन्ध्रप्रदेश) के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री ए० आर० सेमुएल, गुलाम मोहीउद्दीन और एम० रंगैया फिटरों को वर्ग 5 के फिटरों के रूप में पदोन्नत न करने और स्थायी न बनाने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[स० एल०-21011/8/75-डी० ओ० III(बी)]

एम० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 12th February, 1976

S.O. 1426.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited Ramagundam Division, Godavari Khani (Post Office) Karimnagar (District Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narasing Rao shall be Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division II, Godavari Khani Post Office, Karimnagar District (Andhra Pradesh), in not promoting and confirming Sarva Shri A. R. Samuel, Gulam Mohiuddin and M. Rangaiah, Fitters as Category V Fitters is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

[No. L-21011/8/75-D.O. III(B)]

New Delhi, the 30th March, 1976

S.O. 1427.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Pandaveshwar Colliery of M/s. Coal Mines Authority Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th March, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Justice E. K. Moidu—Presiding Officer.

Reference No. 53 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Pandaveshwar Colliery of Messrs. Coal Mines Authority Ltd.,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Absent.

On behalf of Workmen—Sri Ranjan Das Gupta, Organising Secretary of the Union.

State : West Bengal. Industry : Coal Mine.

AWARD

This reference arises out of the Order of the Labour Ministry Government of India, vide No. L-19012/21/74/D.IIIB, dated 26th July, 1975 under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The reference reads :

"Whether the management of Pandaveshwar Colliery of Messrs Coal Mines Authority Limited, Post Office Pandaveshwar, District Burdwan, are justied in stopping from work Sarva Shri (i) Puran Das, (ii) Jittan Gyan, (iii) Sukhu Majhi, (iv) Sulamon Sk., (v) Khara Majhi, (vi) Chowan Majhi, (vii) Garib Majhi, (viii) Diba Majhi, (ix) Nizam Mia and (x) Mahadeb Das, Stopping Mazdoor with effect from 29th March, 1974; If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. Summons to the parties were despatched on 18-8-1975. The Coal Mines Authority acknowledged the summons on 22-8-1975. Afterwards they applied to this Tribunal more than 8 (eight) times for extension of time for filing written statement. But they never filed one. The Union, however, filed their written statement.

3. Another summons was issued to the Coal Mines Authority posting the reference to this date for peremptory hearing. They did not turn up. So they were declared absent.

4. On behalf of the Union its Organising Secretary Sri Ranjan Das Gupta was examined. He proved the claim against the employer.

5. In the result an award is passed in favour of all the workmen mentioned in the Schedule reinstating them to their respective posts as Mazdoors as on the date of their Stopping of work with back wages and all other benefits which they are entitled.

Dated, Calcutta,
The 15th March, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-19012/21/74-LRII/D III(B)]

S.O. 1428.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the New Kenda Colliery of Messrs. Coal Mines Authority Limited, and their workmen which was received by the Central Government on the 23rd March, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA.

Reference No. 49 of 1975

PRESENT :

Justice E. K. Moidu, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the New Kenda Colliery of Messrs. Coal Mines Authority Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri Nikhiles Das, Advocate, with Sri M. Ghosh Chaudhuri, Group Personnel Officer, New Kenda Sub-Area, Area V.

On behalf of Workmen—Sri Basudev Puitandi.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal Mine.

AWARD

This reference arises out of the Order of the Ministry of Labour, Government of India vide No. L-19012/2/75/D.III.B, dated 23rd July, 1975, under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The reference reads :

"Whether the action of the management of New Kenda Colliery of Messrs. Coal Mines Authority Limited, Post Office Toposi, District Burdwan, in retiring Shri N. N. Puitandy, Electrician, with effect from 1st August, 1973 is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the Coal Mines Authority Limited is that the workman Shri N. N. Paitundi retired from service on attainment of superannuation with effect from 1-8-1973. And that he had now put forward a false claim that his age was wrongly assessed and that the correct year of his birth was 1918 According to them the correct year of his birth was 1910. On attainment of more than 63 years of age, the workman retired on receipts of his provident fund and gratuity. Ext. M-1 was his Service card and Ext. M-2 was his identity card. In both those records the year of birth of the workman was shown as 1910. So, they state that the workman had been correctly and legally retired from service. The Coal Mines Authority filed a written statement as early as on 3-9-1975 raising these contentions.

3. The workman did not file any written statement in the case, though he received the summons in the case in August, 1975. When the case came up for hearing today after a notice was issued to the workman posting the case for peremptory hearing, he came with an application stating that the case should be adjourned to another date. I find no substantial ground for an adjournment. So the case was tried taking the evidence of the Coal Mines Authority's witness as MW-1 and that of the evidence of the workman as WW-1. The Coal Mines Authority produced some documents which were marked as Exts. M-1 to Ext. M 4 and the workman's documents were marked as Exts. W 1 to W 6.

4. The main question that arises for determination is whether the workman has proved his correct age in order to ascertain whether his date of superannuation was correctly fixed by the Coal Mines Authority.

5. It is admitted that the date of his superannuation shall be on his attainment of 58 years of age. The records of the Employer show that the year of his birth was 1910. The workman himself was a party to Exts. M1 to M3. He received his provident fund amount and gratuity after his retirement in full discharge of all his claims against the employer. Ext. M-3 was his application for getting the Provident fund amount. He signed it on 3-5-1974. After going through all these processes he was alleged to have got Ext. W-2 certificate from the Headmaster of a Government aided High School of Ethora, Burdwan District, on 29-9-1973. The genuineness of Ext. W-2 was questioned by the employer vide Ext. M-4 letter. That was never answered by the Headmaster. The workman has not taken any step to prove the authenticity of Ext. W-2. At one stage of his examination he stated that he has no personal knowledge of any such register maintained in the High School. The other documents produced by the workman do not help him to fix his correct age. When there are admitted documents in the custody of the Employer regarding the correctness of the age of the workman, it would be difficult to rely upon the workman's documents which are not proved to establish his age. I find no reason to reject the documents or the evidence adduced on behalf of the management. I hold that the correct age of the workman had been fixed and he was allowed to retire in correct time with effect from 1st August, 1973.

6. In the result, the reference is answered in favour of the management and against the workman

An award is passed accordingly.

Dated, Calcutta,
The 17th March, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-19012/2/75-D-III(B)]

S.O. 1429.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs. All India Stone Company, Pakur and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar—Presiding Officer.

Reference No. 90 of 1975

(Ministry's Order No. L-29011/92/75/D. IIIB, dt. 23-7-1975)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs. All India Stone Company, Pakur.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. Ganguly.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Stone Mine.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :—

"(1) Whether the action of the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs All India Stone Company, Pakur in terminating the services of Shri Jayanti Kumar Banerjee, Blaster, in the Malpahari Majoorkola Stone Mine, with effect from the 31st January, 1975, on the ground of unfitness due to old age is justified ?

(2) If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. On receipt of the above order of reference notices were issued to both sides. The employers All India Stone Company, Malpahari Majoorkola Stone Mine, appeared before this Tribunal through their authorised representative. None appeared for the workmen but a petition was received on 8th October, 1975 from the President of Stone Quarry Workers' Union, Pakur praying for time for an indefinite period in view of emergency. The Tribunal was not in a position to grant him an indefinite adjournment on the plea as taken by the President of the Union representing the workmen. The workmen were, therefore, directed to file written statement and complete other steps, failing which the case would be disposed of according to law in the absence of the workman without further notice. Then the case was fixed on 7-11-1975 on which date the authorised representative of the employers appeared and praved for some time to file their written statement. None was present for the workmen nor any step was taken by them. The case was next fixed on 1-12-1975 when the authorised representative of the employers appeared and filed written statement. This time also none was present for the workmen nor any step was taken. Then the case was again fixed on 5-1-76 and 16-2-76 when none was present for the workman nor any step was taken by them. It will, therefore, appear that since the date of order of reference in July, 1975 till 16-2-1976 the workmen or their representative were never present nor took any step in the case. On the last date fixed for hearing a representative from the employers appeared. He submitted that it was the workmen who raised the industrial dispute and the position of the employers was like that of a defendant to the claim of the workmen. In the absence of the workmen all through, the employers do not have any industrial dispute subsisting and they are not interested to proceed with this case any more. There is no reason why the workmen should not take any step all through the pendency of this reference. I am, therefore, inclined to suppose that the workmen are no longer interested to proceed with this case as they have no industrial dispute subsisting at the present moment. There is no indication that the workmen would be coming for their case within a reasonable period. The industrial dispute referred to have thus not been pressed for adjudication by either side. So the matter boils down to this that the parties have no longer any industrial dispute subsisting. I have, therefore, no other option but to pass a 'no dispute award' in this case.

3. In the result, I make a 'no dispute award' in respect of this instant Reference.

Dhanbad, dated, the 19th March, 1976.

K. K. SARKAR, Presiding Officer

[No. L-29011/92/75-D-III(B)]

S.O. 1430.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs. All India Stone Company Pakur and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1976.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar—Presiding Officer.

Reference No. 93 of 1975

(Ministry's Order No. L-29011/93/75/DIIIB, dt. 24-7-1975).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs All India Stone Company, Pakur.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employees—Shri S. Ganguly.

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Stone Mine.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, sent the above reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :—

"(1) Whether the action of the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs. All India Stone Company, Pakur in terminating the services of Shri Shyama Kunai, Machine Mazdoor, in Malpahari Majoorkola Stone Mine with effect from 27th January, 1975 is justified ?

(2) If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. On receipt of the above order of reference notices were issued to both sides. The employers All India Stone Company, Malpahari Majoorkola Stone Mine, appeared before this Tribunal through their authorised representaive. None appeared for the workmen but a petition was received on 8-10-1975 from the President of Stone Quarry Workers' Union, Pakur praying for time for an indefinite period in view of emergency. The Tribunal was not in a position to grant him an indefinite adjournment on the plea as taken by the President of the Union representing the workmen. The workmen were, therefore, directed to file written statement and complete other steps, failing which the case would be disposed of according to law in the absence of the workmen without further notice. Then the case was fixed on 7-11-1975 on which date the authorised representative of the employers appeared and prayed for some time to file their written statement. None was

present for the workmen nor any step was taken by them. The case was next fixed on 1-12-1975 when the authorised representative of the employers appeared and filed written statement. This time also none was present for the workmen nor any step was taken. Then the case was again fixed on 5-1-76 and 16-2-76 when none was present for the workmen nor any step was taken by them. It will, therefore, appear that since the date of order of reference in July, 1975 till 16-2-1976 the workmen or their representative were never present nor took any step in the case. On the last date fixed for hearing a representative from the employers appeared. He submitted that it was the workmen who raised the industrial dispute and the position of the employers was like that of a defendant to the claim of the workmen. In the absence of the workmen all through, the employers do not have any industrial dispute subsisting and they are not interested to proceed with this case any more. There is no reason why the workmen should not take any step all through the pendency of this reference. I am, therefore, inclined to suppose that the workmen are no longer interested to proceed with this case as they have no industrial dispute subsisting at the present moment. There is no indication that the workmen would be coming for their case within a reasonable period. The industiral dispute referred to have thus not been pressed for adjudication by either side. So the matter boils down to this that the parties have no longer any industrial dispute subsisting. I have, therefore, no other option but to pass a 'no dispute award' in this case.

3. In the result, I make a 'no dispute award' in respect of this instant Reference.

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

Dhanbad, dated, the 19th March, 1976.

[No. L-29011/93/75-D.III(B)]

New Delhi, the 5th April, 1976

S.O. 1431.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Parasea Colliery of Messrs. South Parasea Colliery Private Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st April, 1976.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

PRESENT :

Justice E K. Moidu, Presiding Officer.

Reference No 110 of 1971

PARTIES :

Employers in relation to the management of South Parasea Colliery of Messrs South Parasea Colliery Private Limited,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—**Absent.**

On behalf of Workmen—Sri Satyen Banerjee, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal Mine.

AWARD

By Order No. L/1912/93/71-LRII, dated 16th October, 1971, the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour & Employment), Government of India, a dispute between the management of South Parasea Colliery of Messrs. South Parasea Colliery Private Limited and their workmen was referred to this Tribunal under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication. The reference reads :

"1. Whether the action of the management of South Parasea Colliery of Messrs South Parasea Colliery Private Limited, Post Office Kajoragram, District Burdwan in laying off the workmen without compensation with effect from the 29th May, 1971, to the 27th June, 1971, was justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

2. Whether the forced unemployment of the workmen of South Parasea Colliery of Messrs South Parasea Colliery Private Limited, Post Office Kajoragram, District Burdwan by the management with effect from the 28th June, 1971, is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. This tribunal recorded a finding on a preliminary issue inter se between the two unions. One of them took up the matter to the Calcutta High Court in a writ proceedings under Article 226 of the Constitution. On the date of hearing neither party was present at the High Court and hence the writ petition had been dismissed. The matter has come back to this Tribunal for disposal of the reference in accordance with law.

3. Notice of the reference was sent to the Manager, South Parasea Colliery, P.O. Kajoragram, Dist, Burdwan, as well as to the Coal Mines Authority, as employers. The previous employer did not turn up and contest the claim. The Coal Mines Authority contended that they are not liable for any of the claims made by the workmen in the case. The claim arose long before the nationalisation of the coal mines came into existence. So the Coal Mines Authority is not liable for the amount to be fixed as payable to the workmen.

4. On the two points raised in the reference there is only the evidence of one workman examined as witness No. 1. His evidence established that the workmen are entitled to compensation in view of the lay off with effect from 29th May, 1971 ending with 27th June, 1971. The period does not exceed 45 days. The evidence of the workman has to be accepted in the absence of any other counter-evidence. I find that the workmen would be entitled to compensation under the provisions of Sec. 25C of the Industrial Disputes Act, 1947. All the workmen involved would be paid 50 per cent of the total of basic wage and dearness allowance during the period when the lay off was in force. The point 1 is answered accordingly.

5. On the second point, here again the evidence of the witness has to be accepted that the workmen were not permitted to work during the period beginning from 28th June, 1971 to 18th August, 1971 when the coal mine was said to have reopened. The workmen claim compensation for this period. But the evidence does not establish that the workmens' claim comes either under Sec. 25F or under Sec. 25FFF. So, the workmen would be entitled to actual wages to which they would be entitled for the period from 28th June, 1971 to 18th August, 1971. The amount so calculated as their total wages during the period shall be paid to them.

6. In the result, an award is passed in favour of the workmen of South Parasea Colliery giving them compensation equal to 50 per cent of their total basic wages and dearness allowance from 29th May, 1971 to 27th June, 1971 and full wages to each of the workman from 28th June, 1971 to 17th August, 1971 and the amount so fixed shall be paid by the erst-while management of the South Parasea Colliery of Messrs. South Parasea Colliery Private Limited Post Office Kajoragram, District Burdwan.

Dated, Calcutta, The 25th March, 1976.

E. K. MOIDU, Presiding Officer

[No. L-19012/93/71-LRII/D-III(B)]

S.O. 1432.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division, (PO) Godavari Khani and their workmen which was received by the Central Government on the 30th March, 1976.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri T. Narasing Rao, M.A.,LL.B., Industrial Tribunal, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 14 of 1975

BETWEEN

Workman of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division, (P.O.) Godavari Khani.

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division, (P.O. Godavari Khani.

APPEARANCES :

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Workmen.

Sri D. Gopala Rao, Member of Chamber of Commerce & Industry of A.P., Hyderabad—for Management.

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour through notification No. L-21012/14/74-LR.II/D.IIIB dated 3rd April, 1975 referred the Industrial Dispute between the employer in relation to Ramagundam Division of Singareni Collieries Company Limited, Godavari Khani, Karimnagar (A.P.) and their Workman under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (which would hereinafter be called the Act) for adjudication by the Tribunal on the following issue :

"Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division, Godavari Khani Post, Karimnagar District, Andhra Pradesh, in not promiting and confirming Shri T. Agaiah, Electrician as Category V Electrician is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 14 of 1975 and notices were directed to the workman and to the employer. In the counter filed by the workman it is inter alia alleged that he was appointed as Electrician in No. 6 Incline, Godavari Khani by the Respondent-Management in November, 1962. He was promoted to Category IV Electrician in 1964. He was entrusted with complete charge of the shift since December 1972 and was being paid Acting allowance of Category V Electrician ever since. It is contended that by the time the dispute was taken up for conciliation he had put in a service of 12 years as Electrician and was also paid Acting Allowance continuously for two years in that category of Electrician V. Since the time he was entrusted independent charge of the duties of Category V Electrician he has been discharging his duties satisfactorily. As per the Tradesmen Agreement dated 4-10-1966 there is said to be a clear vecancy of Category V Electrician in this Incline but the services of this workman were being utilised by the employer-respondent only by paying the Acting Allowance, without confirming the claimant in that post, even though it is a clear vacancy. When this claimant requested for confirmation in Category V the Management is said to have refused to confirm him on the ground that he did not hold requisite qualifications of Trade Certificate from I.T.I., as per the Company's Circular dated 10-6-1970. It is, however, admitted by him that the claimant does not hold a certificate of I.T.I But what is contended is that as per the Tradesmen Agreement dated 4-10-1966 there was no condition that only I.T.I. certificate holders will be eligible for promotion for Category V Electrician. It is alleged that even after the Circular dated 10-6-1970 the Management promoted certain Electricians who were not holding I.T.I. certificates, to Categories V and VI. Sri Abraham is said to have been promoted from Category V to Category VI. Nalli Rayalingam is said to have been similarly promoted from Category V to Category VI. Sri Shankar is said to have been promoted similarly from Category V to VI. Certain other instances are also given by the claimant. These persons are said to have been promoted in the year 1974. But the claimant was unjustly refused confirmation in Category V inspite of the fact that for more than two years his services have been utilised as Category V Electrician. On 17-4-1975 the Management is said to have issued another Circular where-under even though the persons in service do not possess I.T.I. certificates the Electrician and Fitters are held eligible for promotion to higher categories on passing the Trade Test. In view of his long service of 13 years and also having discharged the duties of Vth Category Electrician and in view of this post being a clear vacancy, it is prayed that he may be confirmed as Category V Electrician.

3. In the counter filed by the Management it is admitted that the claimant was appointed on 5-11-1962 and was promoted as Electrician on 7-6-1964. On implementation of the Wage Board Recommendations he was placed in new Category IV with effect from 15-8-1967. It is also admitted that whenever the claimant was asked to officiate as Category V Electrician he was paid allowances. It is, however, alleged that the claimant is not efficient and is, therefore, not eligible for promotion to Category V (Electrician). The General Manager is said to have issued a Circular on 10-6-1970 prescribing the qualification for an Electrician or Fitter, but the Claimant is said to have no such qualifications to be confirmed in Category V. Minutes as per this Circular are said to have been drawn on 29-5-1972 which were also agreed by the Union of the workman. It is thus contended that the claimant is not entitled to be promoted to Category V as he has no qualification and efficiency. It is alleged that in Godavari Khani 6th Incline, there is a Category V Electrician in each shift and therefore, it is denied that the claimant was entrusted with the independent charge of Category V Electrician or that he acted in that capacity from 1972 onwards. It is contended if any Electrician was promoted to Category V after the issue of Circular dated 10-6-1970 it is only on proof of his efficiency. It is also alleged that as per the Circular dated 17-4-1975 Electricians with long service of more than 13 years and who passed the Trade test conducted by the Management are eligible to be promoted to Category V. The claimant is said to have neither long service nor did he pass the Trade Test. That apart, promotion is alleged to be a managerial function. Thus the claim of the claimant is said to be not justified.

4. The workman examined himself in support of his claim as W.W.1. He also relied upon Exs.W1 to W6. Ex.W1 relates to the procedure to be followed with regard to the grievances of the workman. As per the procedure laid down therein, the workman made his representation for confirming him in Category V to the Manager, to the Agent, and to the Chairman of the Grievance Committee. The Manager as per Ex.W3 replied that the case of the workman for promotion cannot be considered as his attendance is irregular and his work is not upto the mark. This letter is dated 27th January, 1974. Under Ex W5 the same view was communicated by the Agent rejecting his claim for promotion. It does not appear that the Chairman of the Grievance Committee has intimated the workman inspite of the latter's representation to him as per Ex.W6. The management in rebuttal examined two witnesses in oral evidence as M.W.1 and M.W.2 and relied upon Exs. M1 to M4. M.W.1 is the Divisional Superintendent at present at Bellampalli Division but was the Manager of Godavari Khani No.6 Incline from 1968 October to 15th December 1974. M.W.2 is the Superintending Mining Engineer of Incline No. 6 for the last one year and four months.

5. It is common case that from 1964 the claimant was working as Category IV Electrician. Consequent to the implementation of the Wage Board recommendations from 15-8-1967 he was assigned new Category IV Electrician. Even from the version of the Management as borne out by Ex.M3 the extract of payment of Acting Allowance, the claimant has been acting in Vth Category from December, 1972. The controversy here is that according to the claimant he has been continuously acting in that category from December 1972 to March 1975, in which month according to the claimant, one Odellu was promoted from Category IV to V and posted in his place It is, however, admitted by M.W.2. that there are three shifts and one general shift in 6th Incline and that during the period from 1972 to 1975 there were only two regular Category V Electricians and this required two acting Category V Electricians. It is also admitted by him that the claimant was officiating but what is sought to be established is that he was not working continuously. It is, however, the very admission of M.W.2 that whenever the claimant was put in the first shift or the general shift no Acting Allowance was given to him. Thus Ex.M3

the extract of payment of allowance does not represent the total number of days worked by this claimant in Category V. It is, however, seen that for the year 1973 the claimant according to M.W 2 was paid allowance for 234 days out of 305 working days in that year. Since Ex. M3 does not represent the correct position of the total number of days, for the reasons stated above, it can as well be said that the claimant continuously worked during that year. Even from the version of M.W 2 in the absence of any other Electrician and four such Electricians being required one for each shift per day it is reasonable to hold that the claiment has been acting in that post as per the requirement of the Management. Thus there is no difficulty in holding, as claimed by the claimant that from December, 1972 to March 1975 he has been working continuosuly in that post. It is also an admitted fact that he was appointed in the year 1962 and by this time he has put in 13 years of service. The only point is that whether in view of his long service and also his officiation in Category V for a period of more than two years, is he eligible for promotion or not.

6. The Management issued Ex. M1 as to the conditions of promotion as early as June 1970. The qualifications for promotion or appointment to Category V Electrician as per this notification are an Electrician Certificate granted by the State Government of Andhra Pradesh or other equivalent recognised certificate. Preference is said to be given to persons who have under gone I.T.I. course and possess the Electrician Certificate. They should also pass the Trade Test for Category V conducted by the Company. It would transpire from the evidence of M.W.1 and Ex. M2 dated 17th December, 1970 that the claimant was sent for Trade Test in the year 1970 but he did not pass. It is also stated in Ex. M2 that the work of the claimant was also not satisfactory and therefore his case for promotion cannot be considered. It is also deposed by M.W.1 that subsequent to that date the claimant was not sent for appearing for any test. It is admitted by the workman also that those who are not having I.T.I. certificate are promoted after the test of their efficiency and that this was being done from the year 1970. What his grievance is that he should have been equally given the opportunity of appearing for a test. But this he was deprived of. It is also conceded by the workman after 1972 a written test is also prescribed. The workman would also put it that he is ready to appear for any efficiency test. Though the Management would put it that the work of this claimant in Category V was not satisfactory, there is nothing to show that it was so. The Management has not filed any record to show that on any prior occasion the claimant was issued any Memo which would indicate that his performance was not satisfactory. The Management would also allege that the claimant was not regular in his attendance. The workman as W.W.1 would allege that even for one day's late attendance he was being charge sheeted. The irregularities in attendance could as well be the matter of some action by the Management under the Standing Orders. But that is far from saying that the work or performance of the claimant is not satisfactory. At any rate the workman has been continuously officiating for more than two years in that category. If his performance resulted in any loss or break out of fire as is sought to be painted by the Management, there could have been some written record of those occasions when the workman could be said guilty of lapses. In the absence of any record filed by the Management I am constrained to hold that the allegation about the unsatisfactory performance of the claimant is devoid of truth. It is not only the case of the Management that the non-I.T.I. personnel are promoted only after a trade test but also admitted by the workman that from 1970 such tests of efficiency are imposed. It is also the admission of the workman that after 1972 written tests are also prescribed. Admittedly the workman does not possess any I.T.I. qualification or the certificate of an Electrician but that in view of his long service and also his experience as Category V Electrician, the Management ought to have given him an opportunity even under the Circular dated 17-4-1975. It is true that these tests are conducted as deposed by M.W.1 as and when the vacancies arose. But as admitted by M.W. 1 the claimant was sent for test in the year 1970 and that too only once. It is relevant to record that he officiated in Category V from December 1972 long after that alleged test. The officiation for a period of two years or more in that category would have afforded sufficient opportunity to the claimant to acquaint himself with the duties of Category V Electrician. As alleged in the counter even as per the Circular dated 17-4-1975 Electricians having more than 13 years of service and passing the Trade Test are admitted to be eligible for promtions. The claimant has by now put in 13 years of service and if an opportunitw is given he may prove his efficiency for being promoted. Though the tests are not held at regular intervals, and such tests being only necessary in the interest of the working of the establishment, and that being a regular feature, all that can be said is that the claimant has to equally go through such a test. Though it is alegel by the claimant that persons like Abraham, Rayalingam and Shankar were promoted though they do not possess any I.T.I. qualifications, the Management has come forward with a letter dated 31 -8-1972 (an unmarked document) to show that Abraham was promoted as a Fitter in Category VI from Category V only on the basis of his passing the Trade Test. The case with regard to Rayalingam appears to be the same. Shankar is also promoted on passing the Trade Test. It cannot therefore, be said that while other Electricians of Category V were promoted this claimant was in any way discriminated. Thus passing of the Trade test as laid down by the Management is a necessary condition for promotion. The only grievance the claimant can make in the circumstance is that he should also be sent for such a test and given an opportunity to prove his efficiency. As noted above, even as per the Circular 17-4--975 the claimant has put in 13 years of service by this date. The only other condition for his promotion is that he should pass the Trade test. The claimant rightly makes grievance of the fact that unless he is sent for such a test he cannot by himself take it. Thus, in the circumstances, the only direction to the Management would be to send this claimant for a test within a period of six months. I am sure that in view of his experience the workman would be competent to prove his efficiency and would pass the test. I am equally hopeful that the Management unimindful of this litigation would give him a fair chance and would consider his case being un-influenced by this litigation and without any prejudice. Though the reference is answered holding that the non-conconfirmation of the workman, by this time cannot be said to be unjustified in view of his not passing the Trade Test for no fault of his, that finding is subject to the observations that the Respondent-Management would send the claimant-workman for a Trade test within six months from this date and thus give him the opportunity of proving his efficiency and thus qualify himself for promotion to Category V.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of his Tribunal, this the 26th day of February, 1976.

T. NARASING RAO, Presiding Officer
INDUSTRIAL TRIBUNAL.

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined For Workmen :

WITNESSES EXAMINED FOR MANAGEMENT

W.W. 1 Shri T. Agaiah.

M.W. 1 Sri K. H. Wakade.

M.W. 2 Sri N. B. Krishna Murty.

LIST OF DOCUMENTS EXHIBITED FOR WORKMEN

Ex. W1 Minutes of discussions held on 22-1-1974 at Godavari Khani between the representatives of both the parties.

Ex. W2 Representation of Sri T. Agaiah dt. 24-1-1974 made to the Manager, Godavari Khani No. 6 incline, Ramagundam Division II, with regard to his confirmation in the Vth Category.

Ex. W3 Reply of the Manager, Godavari Khani No. 6 Incline dt. 27-1-1974 to the representation of Sri T. Agaiah dt. 24-1-1974, refusing to confirm in category Vth.

Ex. W4 Representation of Sri T. Agaiah, dt. 31-1-1974 made to the Agent, Ramagundam Division II, with regard to his promotion in the Vth category.

EX. W5 Reply of the Agent, Ramagunwam Division II, dt. 24-2-71 to the representation of Sri T. Agaiah dt. 31-1- 1974 refusing to promote in category Vth.

Ex. W6 Representation of Shri Agaiah dt. 22-3-74 made to the Chairman Crevence Committee, Ramagundam Division, requesting to confirm in category Vth.

List of Documents Exhibited for Management

Ex. M 1 Circular dated 10-6-1970 of the General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem, in respect of the charges in the service conditions.

Ex. M 2 True copy of the letter dated 17-12-1970 of the Manager, Godavari Khani No. 6 Incline, to the Agent R. G. H., in respect of his remarks against P. Mallaiah and T. Ageaiah, Category IV Electricians of Godavari Khani No. 6. Incline.

Ex. M 3 Acting particulars extract for the period from 1972 to 1975 in respect of Sarvashri T. Aguiah, Pulikanti Mallaiah and M. Ramaiah, Electricians.

Ex. M4 Acting Allowance Register for the year 1974.

[No. L-21013/14/74-LRII/D-III(B)]

T. NARASING RAO, Industrial Tribunal

S. H. S. IYER Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976

का०आ० 1433—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वैस्टर्न रेलवे कैरेज वर्कशाप्स कैन्टीन, परेल और महालक्ष्मी, बम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या वैस्टर्न रेलवे कैरेज वर्कशाप्स कैन्टीन, परेल और महालक्ष्मी, बम्बई के श्रमिकों की (i) महंगाई भत्ता मंजूर करने और (ii) सवेतन बीमारी की छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने की मांगें न्यायोचित हैं ? यदि हां, तो कर्मकार किन अनुतोषों के हकदार है ?

[सं० एल-41012(62)/72-एल० आर० III/डी०II/(बी)]

ORDER

New Delhi, the 4th February, 1976

S.O. 1433.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Western Railway Carriage Workshops Canteen, Parel and Mahalaxmi, Bombay, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2). Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demands of the workmen of the Western Railway Carriage Workshops Canteen, Parel and Mahalaxmi, Bombay, for (i) grant of dearness allowance, and (ii) for grant of sick leave and casual leave with wages, are justified? If so, to what reliefs are the workmen entitled ?

[No. L-41012/62)/72-LR. III/D.II(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1976

का० आ० 1434.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एक ओर भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल सेम्बानार-कोयल और श्री मुथुस्वामी अय्यर, ठेकेदार, 32, अन्दारस्ट्रीट, तिरुचि के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्रीरू टी० पालानीअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल सेम्बानार-कोयल के नैमित्तिक कामगारों अर्थात् श्री थुलासी दास, श्री के० नटराजन, श्री टी० एम० बालासुब्रामण्यम् और श्री गुणासेखरन जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमाणपत्र धारी हैं और जिनकी एक वर्ष या अधिक अवधि की सेवा है, को प्रचालकों के ग्रेड का वेतन दिया जाना चाहिये ? यदि हां तो किस तारीख से ?

(2) क्या भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल, सेम्बानारकोयल के नैमित्तिक कामगारों अर्थात् श्री ए स० बालासुब्रामण्यम श्री के० चन्द्र, श्री डी० मनीवानन, श्री पानीरसेल्वम् श्री चन्द्र शेखरन्, श्री पोनमुथु और श्री के० त्यागराजन, बायलर परिचर प्रमाणपत्रधारियों को बायलर परिचर का ग्रेड दिया जाना चाहिये ? यदि हां तो किस तारीख से ?

(3) क्या भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल सेम्बानार-कोयल में नियोजित नैमित्तिक कामगार जिन्होंने उक्त मिल में एक वर्ष से अधिक सेवा की है उक्त मिल में नियमित रोजगार के हकदार है ? यदि हां तो किस तारीख से और किस ग्रेड में एवं अन्य किन लाभो के साथ ?

[संख्या एल-42011(1)/75-डी-2(बी)]

ORDER

New Delhi, the 18th February, 1976

S.O. 1434.—Whreas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sembanarkoil and Shri Muthuswamy Iyear, Contractor, 32, Andar Street, Tiruchy, on the one hand and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

(1) Whether the casual workmen of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sembanarkoil, namely, Shri Thulasi Doss, Shri K. Natarajan, Shri T. M. Balasubramaniam and Shri Gunasekharan, holders of Industrial Training Institute Certificate, with one year's service and more, should be designated as Operators and given the grade pay of Operators? If so, from which date ?

(2) Whether the casual workmen of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sembanarkoil, namely, Shri S. Balasubramaniam, Shri K. Chandru, Shri D. Manivannan, Shri Panneerselvam, Shri Chandrasekharan, Shri Ponmuthu and Shri K. Thiagarajan, holders of Boiler Attendant Certificates should be given the Boiler Attendant's grade? If so, from which date ?

(3) Whether the casual workmen employed in the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sembanarkoil, who have put in more than one year of service in the said Mill, are entitled to regular employment in the said Mill? Is so, from what date and with what grade and other benefits?

[No. L-42011(1)/75-D.II(B)]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1976

का० आ० 1435—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 15 नवम्बर, 1975 के पृष्ठ 3988 पर का०आ० 4835, तारीख 18 अगस्त, 1975 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एल-41011/17/73-एल० आर०-3/डी-2(बी) तारीख 18 अगस्त, 1975 में :—

अनुसूची में आए "मुख्य ट्रेन निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "मुख्य टिकट निरीक्षक" पढ़िए।

[संख्या एल-41011/17/73-एल० आर० III/डी० II (बी)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th February, 1976

S.O. 1435.—In th notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. L-41011/17/73-LR.III/D.II-(B), dated the 18th August, 1975, published as S.O. 4835, dated the 18th August, 1975 on page 3988 of the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 15th November, 1975 :—

For the words "Chief Train Inspector" occurring in the Schedule, read "Chief Ticket Inspector".

[No. L-41011/17/73-LR.III/D.II(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

का० आ० 1436—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल थंजावुर और श्री पी० एल० सिंगारम ठेकेदार थंजावुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानिअप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या भारतीय खाद्य निगम की थंजावुर स्थित माडर्न राइस मिल में नियोजित आकस्मिक श्रमिक उक्त मिल में नियमित नियुक्ति के हकदार है ? यदि हां तो किस तारीख से और किस वेतनमान या वेतनमानों में और किन अन्य लाभों के साथ ?

[सं० एल-42011/22/75-डी० 2 (बी)]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1976

S.O. 1436.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Thanjavur and Shri P.L. Singaram, Contractor, Thanjavur on the one hand and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the casual workmen employed in the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India at Thanjavur, are entitled to regular appointment in the said Mill? If so, from what date and with what grade or grades of pay and other benefits ?

[No. L-42011/22/75-D.II(B)]

New Delhi, the 31st March, 1976

S.O. 1437.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Cantonment Board, Ambala Cantonment and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th March, 1976 :—

ARBITRATION AWARD GIVEN BY SHRI J. L. WADHI, ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) KANPUR AND ARBITRATOR UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN THE MATTER OF DISPUTE BETWEEN THE MANAGEMENT OF CANTONMENT BOARD, AMBALA AND THEIR WORKMAN REPRESENTED BY ALL INDIA CANTONMENT BOARD EMPLOYEES FEDERATION, AMBALA CANTT.

PRESENT : Shri J. L. Wadhi, Assistant Labour Commissioner (C) & Arbitrator, Kanpur.

Representing the Management :

Shri K. R. A. N. Ayer, Executive Officer, Cantonment Board, Ambala Cantt.

Representing the Workmen :

Shri J. D. Bakshi, General Secretary, All India Cantt. Board Employees Federation, Ambala Cantt.

The Executive Officer, Cantonment Board, Ambala and All India Cantonment Board Employees Federation, Ambala Cantt. by an agreement dated 30th June, 1975 agreed to refer an Industrial Dispute existing between them over the issue of alleged denial of proper scale of pay i.e. Rs. 400—1100 to Dr. C. R. Bhattacharjee w.e.f. 1-2-1969 to my arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947. The Government of India in the Ministry of Labour in persuance of the provision of Section 10A(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 published the said arbitration agreement vide Notificatiodn No. L-13012/2/75-D.IIB dated the 23rd July, 1975. The parties extended the time for giving my award by another period of three months. The following specific matter in dispute was referred to my arbitration.

"Whether the action of the management of the Cantonment Board, Ambala in denying Dr. C. R. Bhattacharjee the scale of pay of Rs. 400—1100 w.e.f. 1-2-1969 is legal and justified ? If not, to what relief is he entitled ?".

The parties were asked to file their written statement of claims and accordingly the written statement of the workman was received by me on 7th August, 1975 and the management was received on 25th October, 1975. The hearing in this case was held on 23-9-1975 when the management desired to file their written arguments within a fortnight. The same were received on 25th October, 1975. The final hearing in this case was held on 12-12-1975.

The case of Dr. C. R. Bhattacharjee is that he is employed by the management of Cantonment Board, Ambala for the last 10 years as an Assistant Surgeon. He was appointed in the grade of Rs. 250—550 with 5 advance increments keeping in view with his past experience and at present is placed in the revised grade of Rs. 350—600.

The union's contention is that Dr. Bhattacherjee was appointed in the grade of Rs. 250—550 and according to the National Tribunal Award the rules of the State Government are applicable to the employees of Cantonment Board as far as the pay scale are concerned. The State Government has revised the grade of Rs. 250—550 to Rs. 400—1100 for their employees and according to them Dr. Bhattacharjee is eligible for the grade of Rs. 400—1100 as he has more than 10 years service at his credit.

In support of this union has made reliance on the letter of Director of Health Service, Haryana's letter No. F-II-2-71 876/2443 dated 27-1-1971 copy of which they have filed along with their written statement The main jist of the letter is as under:—

"The qualifications prescribed for requirement to H.C.M. Class II in the scale of pay of Rs. 400—30—700/4—1100 are as under :—

1. M.B.B.S.

2. Registered with Punjab Medical Council.

25 per cent vacancies in the cadre of H.M.C. II are fill led by promotion on the basis of seniority cum-merit from A.M.O.'s having 5 years permanent service at their credit for whom the qualification for recruitment is medical licenciate."

The management contended that Dr. Bhattacharjee was working as Assistant Surgeon in their hospital at Ambala and was appointed in the scale of Rs. 250—550 with five increments. The scale for M.B.B.S. doctors at that time was Rs. 250—750 and the grade given to Dr. Bhattacharjee was that of a licenciate doctor. Later on Dr. Bhattacharjee was given the revised scale of Rs. 350—600 as applicable to Haryana State for L.S.M.F. as per National Tribunal Award. Since the Award was fully implemented, the grade of 400—1100 can not be given to Dr. Bhattacharjee. The management filed two letters issued by the Director of Health Services, Haryana in support of their case. The jist of one letter dated 25-2-1974 is as under :—

"The promotion of A.M.O. to the post of Medical Officer is not automatic on the completion of 12 years service. It is subject to other factors such as availability of vacancies in H.C.M.S.-II, quota, past performance, seniority etc. for the purpose of counting 12 years continuous service, for 12 years it has to be in the cadre of A.M.O. under Punjab/Haryana Government.

The second letter dated 27-1-1971 referred to by the management is the same which the union has referred and the jist has aleady been reported earlier. The management further stated that Dr. Bhattacharjee does not come under the quota of 25 per cent and also there was no vacancy as such the claim is incorrect and untenable.

In view of the contentions put forward by both the parties it is to be seen whether Dr. Bhattacharjee is eligible for the scale of Rs. 400—1100 or not? The parties have stated that Dr. Bhattacherjee is a licenciate doctor and both the parties have made reliance on the letters issued by the Director of Health Services, Haryana State. From these letters it will be seen that the grade of Rs. 400—1100 is given to M.B.B.S. Doctor on direct recruitment and to a licenciate doctor with 12 years service at his credit on promotion. In the letter produced by the union the licenciate Doctor with 5 years services at his credit is eligible for promotion to this grade. The point is whether Dr. Bhattacherjee can be eligible to the grade automatically or other pre-requisit are essential to get his grade.

Both letters of the Director of Health Services lays down hat the grade of Rs. 400—1100 can be given to the licenciate doctor on promotion. The other requirements is that there should be a post against which one should be considered for promotion. In this case there was no post for which Dr. Bhattacherjee can be considered for promotion and the pre-requisits are not fulfilled as such Dr. Bhattacharjee could not be considered for promotion and is not eligible for the grade of Rs. 400—1100.

In view of the above facts I find that the action of the management in denying the grade of Rs. 400—1100 to Dr. Bhattacherjee is justified and he is not entitle to any relief. The parties will bear their own cost.

Award is passed accordingly.

J. L. WADHI, Assistant Labour Commissioner (Central)

Kanpur, the 25th March, 1976

[No. L-13012(2)/75-D-II(B)]

New Delhi, the 3rd April, 1976

S.O. 1438.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 30th March, 1976.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 36 of 1975

PRESENT :

Sri T. Narasing Rao, M.A., LL.B. Industrial Tribunal, Hyderabad.

BETWEEN

Workman of Nuclear Fuel Complex, Moula Ali, Hyderabad.

AND

The Management, Nuclear Fuel Complex, Moula Ali, Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri I. A. Naidu, Advocate—for Management.

None present—for Workman.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, through Notification No. L-42012(10)/75-D. IIB dated 26th July, 1976 referred the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Nuclear Fuel Complex, Moula Ali, Hyderabad and their Workman, under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (which would hereinafter be called the Act) for adjudication by the Tribunal on the following issue :

"Whether the management of Nuclear Fuel Complex, Moula Ali, Hyderabad, is justified in treating Shri R. P. Kala, Helper 'B' to have abandoned his employment with effect from the forenoon of 5-10-1974, and in refusing to take him in employment ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The reference is registered as Industrial Dispute No. 36 of 1975 and notices were directed to the workman as well as to the Management. The workman filed a claims statement, inter alia alleging that he was originally appointed as Watchman with effect from 4-8-1972 and later he applied to the post of Helper 'B' in the same establishment when a vacancy arose. He was thus selected and appointed as helper 'B' in Zirconium Sponge Plant with effect from 8-11-1973. It is further alleged that on account of the effect of chlorine gas where the workman was working, he contacted eosinophillia from 5-10-1974. On 6-10-1974 he submitted his leave application to the Administrative Officer of the Respondent-Management intimating it about the treatment he was under-going. It is further alleged that he again submitted an application under registered acknowledgement enclosing a medical certificate duly attested by Civil Surgeon, Osmania General Hospital. On his recovery, he reported to duty on 28-12-1974 with a medical fitness certificate, but he was not allowed to join duty and he was informed that his services stood terminated as per a letter dated 15-11-1974. It is, however, contended that the said letter was never served on him. But on 28-12-1974 that order was served upon him and his signature was obtained on a plain paper. On the same day he made a representation and again on 11-1-1975 he contacted the Administrative Officer but he refused to accept the second application, and therefore, he sent it through registered post. Nothing is alleged in these claims statement about the outcome of the second petition or the representations. All that is he prayed for is that the Tribunal should intervene in the matter and do justice to him and to reinstate him with continuity of service, with back wages from 28-12-1974.

3. In the counter filed by the Respondent, it is contended that the services of the claimant-workman were not terminated at all as it was a case of abandonment of service and loss of lien as per the Standing Orders. The reference under Section 10 is said to be bad and thus the Tribunal has no jurisdiction to entertain or adjudicate the industrial dispute. It is admitted that the claimant was initially appointed as a watchman and was subsequently appointed as Helper 'B' with effect from 15th December, 1973 but not from 8th November, 1973 as alleged in the claims statement. It is, however, admitted that he was posted to work in Zirconium Sponge Plant of the Respondent-Management. It is emphatically denied that the claimant-petitioner or any other workman in the said Plant was affected by chlorine gas. The plant is said to have been designed according to international standards and based on experience gained, obviating any health hazards like radio activity, powder flying etc. It is also contended that no other workmen of this Plant ever complained of any ill-effects on account of chlorine gas. It is denied that the Respondent ever submitted an application nor sent it through post on October 6, 1974. The only communication that was received from the workman was on 13th December, and that was a medical certificate dated 22nd November, 1974 issued by an Asst. Civil Surgeon and countersigned by the Civil Surgeon of the Osmania General Hospital. The dates in the said certificate are said to be conflicting, altered and corrected and, therefore, it was considered not to be a genuine certificate As there was no leave application from the claimant, on 26th October, 1974, on account of unauthorised absence of the workman from 5th October, 1974, onwards a Memo was sent to the claimant drawing his attention to Clause 34 of the Standing Orders and requiring him to report to duty immediately. That Memo was sent in the usual course by ordinary post. Since the said letter was not returned to the sender, it is alleged that the claimant must have received it. Since the claimant had not joined inspite of this Memo and continued to be absent till November 15, 1974, a letter was addressed by the Respondent to the claimant notifying that the claimant automatically lost his lien on his employment as per Standing Order Clause No. 34. This letter was sent to the address of the claimant as furnished by him in his earlier applications, under acknowledgement due, but it was returned by the Postal authorities with the endorsement 'left' The copy of the same letter was sent on December 9, 1974 by registered post to the permanent town address of the claimant in Rayadurg, Srinagar District. That letter was mistakenly received by another R. C. Kala who later returned it to the Management as per its request. It is also contended by the Management that the Petitioner did not furnish any leave address or intimated the Management about the change of his address though there was a duty cast upon him as per Clause 11 of the Certified Standing Orders. It is, however, admitted that on 28th December, 1974 the claimant approached wilth a medical fitness certificate and another medical certificate upto 27th December, 1974. The contention is that since the lien of the claimant on his employment stood automatically terminated he could not be taken on duty. The representation made by the claimant on the said date and a later communication sent by him dated 11-1-1975 had to be rejected on a careful scrutiny of the material. In short it is alleged that what was intimated to the claimant under the various orders is only the automatic loss of his lien on the post and not that his services were terminated by a positive act of the Management. It is, further alleged that the claimant was an Army Reservist but instead of being disciplined his performance is far from being a disciplined one. It is also alleged that the Respondent was running a shop attached to his father-in-law's residence at Lalaguda after he abandoned his service. It is reiterated that since no order of termination was passed by the Management there is no industrial dispute and that the Tribunal is not competent to adjudicate upon this reference.

4. After the Respondent filed his counter the workman was not present on two hearings, therefore, a notice was again directed to him which was also served. Inspite of service notice for the hearing on 21-1-1976 the workman was absent. The case was adjourned finally to 17-2-1976 for enquiry. The claimant-workman sent a petition through post stating that he is not in a position to move and that the Tribunal should decide for itself and intimate the result to him. The Management, however, sought time to lead evidence. Thus M.W. 1 the Industrial Relations Officer, examined himself in support of the averments of the counter.

5. The evidence of M.W. 1 and records are perused. The evidence of M.W. 1 is that no leave application whatsoever was received from the claimant on 6th October, 1974, and the first communication received is a medical certificate on 13th December, 1974. The workman filed a certificate of posting dated 6-10-1974 under which a cover is said to have been addressed to the Administrative Officer. It is also not the case of the workman that on 6-10-1974 he enclosed any medical certificate to the leave application. The evidence of M.W. 1 is that a panel of 39 doctors are spread over the twin cities who could be approached by the sick workman. If really the workman was suffering from any disease such as eosinophillia, nothing prevented him from approaching the Company's Doctor. The claimant has also not gone into

the witness box to swear in support of the allegation that he sent an application on 6th October, 1974. On the other hand the positive evidence of M.W. 1 is that no leave application was received. Even before the first medical certificate was sent by the claimant the office of the Respondent-Management after waiting for 14 days is said to have sent a letter on 26th October, 1974 drawing the attention of the claimant to Clause 34 of the Standing Orders and calling upon him to join duty immediately. As the claimant workman did not join duty even thereafter, on 15th November, 1974 he was notified through a letter that he lost his lien over the job It is true that admittedly that letter could not be served on the workman though the Respondent-Management even tried to effect its service by sending it through registered post on his home town address as furnished by the workman-claimant. Non-service of this letter as is borne out by the records and as also admitted by the Management cannot be held to be a factor against the Management. It is equally necessary to note that it is not the case of the workman that the Management bore any grudge against him or that the action of the Management, if any, was by way of victimisation. There is no reason to believe that the Management has suppressed the alleged leave application sent by him initially. There is nothing on record to show that the workman has by another leave application sought extension of leave. On the other hand, the Management has well preserved the communications sent by the claimant. The medical certificate sent by him is part of the record. While a leave of 49 days is recommended the date from 5-10-1974 to 22-11-1974 is altered to 5-10-1974 to 18-12-1974. That certificate is issued by an Asst. Civil Surgeon, though counter-signed by the Civil Surgeon of the Osmania General Hospital. It is rightly contended by the Management that the alteration of the dates do not correspond to the number of days in the said certificate and if petitioner could move from Secunderabad to Dabirpura in Hyderabad he could have as well approached the Company's Doctor if in fact he was suffering from any disease. The contention of the Management that it is a spurious medical certificate is not devoid of truth.

6. It is now to be seen whether the Standing Orders of the Company provide for the automatic termination of the lien. Clause 34 of the Standing Orders reads as follows :—

> "If a workman remains unauthorisedly absent for 14 days or more, such a workman will be deemed to have abandoned the employment voluntarily. NFC Management may review such cases at its discretion depending upon the circumstances and reserve the right whether or not to re-employ him and if re-employed, on such service condition as it may consider fit."

It can be recalled that in view of the un-authorised absence of the workman from 5th October, 1974 the Management issued a Memo on 26th October, 1974 itself drawing the attention of the workmen to this Clause. When the workman persisted in his absence till 15th November, 1974 he was notified about the automatic loss of lien. All these letters emanated from the Management even before the first medical certificate was received by it from the claimant. In the absence of any oblique motive attributed to the Management, it can only be said that there was no leave application before it whatsoever and therefore, the claimant was informed of the automatic loss of his lien even by 15th November, 1975. As noted above, the letter notifying the loss of lien could not however be served upon him. But that is not due to the fault of the Management. The Standing Order referred to above lays down in clear terms that the un-authorised absence would be deemed to have resulted in the abandonment of employment. There is no positive act of passing an order of termination by the Management. Even though where the Management artfully couches an order of discharge or dismissal as an order of termination simpliciter the Tribunal would be competent to go beyond the order and find out its true nature But such a situation does not arise in this case. It is held in Buckingham & Carnatic Co. v. Venkatiah (AIR 1964 Supreme Court, page 1272) :

> "Whether termination of the employees services follows automatically either from a contract or from a Standing Order by virtue of the employee's absence without leave for the specified period, such termination is not the result of any positive act or order on the part of the employer."

It is similarly held in N. E. Industrial v. Hanuman (1968 Supreme Court page 83):

> "Whether a workman's service terminates automatically under the Standing Orders, Section 33 would not apply . . . . . .
>
> Where a Standing Order provides that a workman losses lien on his appointment, if he does not join duty within certain time after his leave expires it only means that his service stands automatically terminated when the contingency happens."

Thus as per the Standing Orders referred to above the workman has lost his lien in view of un-authorised absence for more than the minimum period of 15 days. In view of the attempt of the workman to procure a medical certificate which on account of its suspicious nature throws doubt about his being really ill, the Management is not bound to re-consider his re-employment. That apart, it is not only the averment of the counter but also the evidence of M.W. 1 that during the course of conciliation the workman expressed no anxiety at all about the loss of his job, as he is running a small shop. The attitude of the workman displayed presently by sending a letter that the case may be decided on merits and his continuous absence before the Tribunal without caring to establish his allegations would also indicate that the workman is not keen in prosecuting his case. Thus there is no reason to call upon the Management either to reinstate or to re-employ him on any condition. The dismissal of his representation by the Management in the above circumstances appears to be justified. M.W. 1 would also aver that the claimant-workman inspite of being an Army Reservist was not disciplined and was not regular in his attendance and was a matter of anxiety. Considering this circumstance also there does not appear to be any ground directing the re-employment of the workman. In short, the workman is not entitled to any relief and his claim is, therefore, rejected. The reference is answered holding that the Management was justified in treating the workman as having abandoned the service voluntarily, in the light of Clause 34 of the Standing Orders.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 23rd February, 1976.

T. NARASING RAO, Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined for Workmen :

NIL.

Witnesses Examined for Management :

M.W. 1 E. Raja Manikyam.

List of Documents Marked for Workmen :

NIL

List of Documents Marked for Management :

NIL

T. NARRASING RAO, Industrial Tribunal.

[No. L-42012/10/75/D-II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1976

का० आ० 1439.—भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2452 तारीख 9 अगस्त, 1973 के साथ प्रकाशित, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थान आवण्टन नियम, 1973 में,--

"कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थान आवंटन नियम, 1973" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आए हैं,

"कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी निवास-स्थान आवटन नियम, 1973" शब्द और अंक पढ़े।

[सं० ए० 12011/108/74-फैक]

नई दिल्ली, 18 मार्च 1976

का० आ० 1440—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण मे, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 2079, तारीख 8 जुलाई, 1965 को अधिक्रांत करते हुए, निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन रहते हुए और जब तक और आदेश नही किए जाते, दिल्ली, चण्डीगढ़, गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, पाण्डीचेरी और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्रो के प्रशासक (चाहे वे उप राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक के रूप मे ज्ञात हो) अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 (1962 का 59) की धारा 2 की उपधारा (2) और (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्यो का निर्वहन करेंगे।

[सं० एस० 19025/12/71-एफ०ए० सी०]

New Delhi, the 18th March, 1976

S.O. 1440—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and employment No. S. O. 2079 dated the 8th July, 1965, the President is pleased to direct that subject to his control and until further orders, he Administrators (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator) of the Union Territories of Delhi, Chandigarh, Goa Daman and Diu, Lakshadweep, Dadar and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Pondicherry and Mizoram, shall, within their respective territories, discharge the functions of the Central Government under sub-sections (2) and (7) of section 2 of the Personal Injuries (Emergency Provisions) Act, 1962 (59 of 1962).

[No. S-19025/12/71-Fac.]

का० आ० 1441—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2402 तारीख 26 जुलाई, 1965 को अधिक्रांत करते हुए, निदेश देते है कि उनके नियंत्रणाधीन रहते हुए और जब तक और आदेश नही किए जाते, दिल्ली, चण्डीगढ़, गोवा, दमण और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अन्दमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, पाण्डीचेरी और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे वे उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक के रूप मे ज्ञात हों) अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962 (1962 का 59) की धारा उपधारा (2) और (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्यों का निर्वहन करेंगी।

[सं० एस० 19025/12/71-एफ० ए० सी०]

S.O. 1441.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of the Notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S. .O 2402 dated the 26th July, 1965, the President hereby directs that the Administrators (whether known as Lieutenant Governor, Chief Comissioner or Administrator) of the Union Territories of Delhi, Chandigarh, Goa, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Pondicherry, and Mizoram, shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise of the powers and discharge the functions of the Central Government under sub-sections (2) of section 3 of the Personal Injuries (Emergency Provisions) Act, 1962 (59 of 1962) within their respective territories.

[No. S. 19025/12/71-Fac.]

का० आ० 1442.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 2078 तारीख 8 जुलाई, 1965 को अधिक्रांत करते हुए, वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 (1962 का 59) की धारा 2 की उपधारा (2) और (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्यों, राज्य सरकारों को, उनकी सम्मति से, सौंपते हैं।

[स० एस० 19025/12/71-एफ०ए० सी०]

S.O. 1442.—In pursuance of clause (1) of article 258 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S. O. 2078 dated the 8th July, 1965, the President is pleased to entrust to the State Governments, with their consent, the functions of the Central Government under sub-sections (2) and (7) of section 2 of the Personal Injuries (Emergency Provisions) Act, 1962, (59 of 1962).

[No. S. 19025/12/71-Fac.]

का० आ० 1443.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2401 तारीख 26 जुलाई, 1965 को अधिक्रांत करते हुए, वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 (1962 का 59) की धारा 2, की उपधारा (2) और (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य, राज्य सरकारों को, उनकी सम्मति से, सौंपते हैं।

[सं० एस० 19025/12/71-एफ० ए० सी०]

एस० एन० सक्सेना, विशेष-कार्य अधिकारी

S.O. 1443.—In pursuance of clause (1) of article 258 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2401 dated the 26th July, 1965, the President hereby entrusts to the State Governments, with their consent, the functions of the Central Government under sub-section (2) of section 3 of the Personal Injuries (Emergency Provisions) Act, 1962 (59 of 1962).

[No. S. 19025/12/12/71-Fac.]

S. N. SAXENA, Officer on Special Duty.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1976

का० आ० 1444—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, सचिव कर्नाटक सरकार, समाज कल्याण और श्रम विभाग को, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 236 तारीख 16 दिसम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्--

उक्त अधिसूचना में, मद 11 के सामने, प्रथम स्तंभ में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्--

"सचिव, कर्नाटक सरकार,
समाज कल्याण और श्रम विभाग,
बंगलौर।"

[संख्या बी०-20012(1)/75-पी० एफ०-2]

New Delhi, the 29th March, 1976

S.O. 1444.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Family Pension Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints the Secretary to the Government of Karnataka, Social Welfare and Labour Department, as a member of the Central Board of Trustees, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 236 dated the 16th December 1975, namely :—

In the said notification against item 11, for the existing entry in the first column, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Secretary to the Government of Karnataka, Social Welfare and Labour Department, Bangalore."

[No. V-20012(1)/75-PF.II]

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1976

का० आ० 1445.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी बीमा अधिनियम (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, कानपुर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:--

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उससे अपेक्षित थीं,

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो--

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों का सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को नकदी और वस्तु के रूप में पाने का हकदार बना रहता है जिनको ध्यान में रखते हुए इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबन्ध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त किया जाएगा कि वह--

(v) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करेगा कि वह उसे ऐसी सूचना दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपेक्षा करेगा कि लेखे बहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक को प्रस्तुत करने, और उसकी परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करे या उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करें, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तैयार करे या उससे उद्धारण ले।

[सं० एम०-38014/14/75-एच०आई०]

New Delhi, the 3rd April, 1976

S.O. 1445.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act (34 of 1948), the Central Government hereby exempts Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur from the operation of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2 The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory.

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S. 38014/14/75-HI]

का०आ० 1446—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 236 तारीख 16 दिसम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद 21 के सामने, प्रथम स्तंभ में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला।"

[सं० बी०-20012(1)/75-पी० एफ० I]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 1446.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 5A of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Simla, as member of the Central Board of Trustees, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O 236, dated the 16th December, 1975, namely :—

In the said notification, against item 21, for the existing entry in the first column, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Simla".

[No. V-20012(1)/75-PF.I]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1976

का० आ० 1447—भारत सरकार के उस समय के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1780, तारीख 19 जून, 1963 द्वारा गठित केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय, जयपुर के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है,

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना को 16 फरवरी, 1976 से उक्त श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा० सं० एस० 11025/9/76-डी०आई०ए०]

(एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

New Delhi, the 6th April, 1976

S.O. 1447.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the presiding officer of the Central Government Labour Court, Jaipur constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1780 dated the 19th June, 1963.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Rajendra Prasad Saxena as the Presiding Officer of the said Labour Court with effect from the 16th February, 1976.

[F. No. S-11025/9/76/DIA]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.